

My Notes.....

राष्ट्रीय

सवर्णों को 10% आरक्षण मिला

संसद ने सवर्ण जातियों को 10 फीसद आरक्षण के फैसले पर मुहर लगा दी है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार का यह एक ऐतिहासिक फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया था। कई राज्यों में सवर्ण आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं।

1. केंद्र और राज्यों में पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 22 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है।
2. मोदी सरकार सवर्णों को आरक्षण देने के लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव किया जाएगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
3. पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून में बदलाव करने का आदेश दिया था तब देशभर में दलितों ने काफी प्रदर्शन किया था। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था।

क्यों कहता है अनुच्छेद 15

1. संविधान में अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
2. अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है।
3. हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है।
4. इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है, क्योंकि इसमें वर्णित वर्गों के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है।

अनुच्छेद 16 में ये हैं प्रावधान

1. अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।

इन सवर्णों को मिलेगा आरक्षण का लाभ

1. मोदी सरकार के इस एलान से उन सभी को लाभ मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम और 5 लाख से कम की खेती की जमीन होगी।
2. इसके अलावा आरक्षण का लाभ उठाने वाले सवर्णों के पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो, निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो, 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो और जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे।

2. किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।

डीएनए तकनीक बिल लोकसभा से पास

अपराधियों, सदिग्धों, विचाराधीन कैदियों, लापता बच्चों और लोगों, आपदा पीड़ितों एवं अज्ञात रोगियों की पहचान के लिए डीएनए बिल लोकसभा में पास कर दिया गया। डीएनए तकनीक के इस्तेमाल के लिए इस बिल में एक डीएनए लैबरेटरी बैंक स्थापित करने के साथ डीएनए डेटा बैंक स्थापित करना भी है।

क्या है

1. डीएनए आधारित फॉरेंसिक टेक्नॉलजी का प्रयोग अपराधों को सुलझाने में किया जा सकता है। इस तकनीक से लापता लोगों, बिना पहचान वाले मृतकों, बड़ी आपदाओं में अधिक संख्या में हुई मृतकों की पहचान में काफी उपयोगी होता है।
2. डीएनए तकनीक का प्रयोग सिविल केस सुलझाने के लिए भी किया जा सकता है जिनमें बच्चे के जैविक माता-पिता की पहचान, इमिग्रेशन केस और मानव अंगों के ट्रांसप्लांट जैसे कुछ महत्वपूर्ण आयाम शामिल हैं।

इन कारणों से डीएनए की है जरूरत

1. इस बिल की जरूरत डीएनए डेटा बैंक नहीं होने के कारण खास तौर पर थी। इस वक्त करीब 3000 केस डीएनए प्रोफाइलिंग के हैं और लैबरेटरी में डीएनए डेटा बैंक नहीं होने के कारण इन्हें स्टोर करने की कोई सुविधा नहीं है।

डीएनए का रहस्य सुलझाने वाले हरगोविंद खुराना की अनसुनी बातें

1. हमारे डीएनए के आवश्यक कार्य और प्रथम सिंथेटिक जीन के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक डॉ. हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी, 1922 को हुआ था।
2. उन्होंने पता लगाया कि हमारे डीएनए में मौजूद न्युक्लियोटाइड्स की स्थिति से तय होता है कि कौन से अमिनो एसिड का निर्माण होगा।
3. ये अमिनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं जो कोशिकाओं की कार्यशैली से जुड़ी सूचनाओं को आगे ले जाने का काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने पूरी तरह से कृत्रिम जीन का निर्माण किया था।
4. हरगोविंद खुराना का जन्म अविभाजित भारत के रायपुर (जिला मुल्तान, पंजाब) नामक स्थान पर 9 जनवरी 1922 में हुआ था। उनके पिता एक पटवारी थे। अपने माता-पिता के चार पुत्रों में हरगोविंद सबसे छोटे थे।
5. सन 1960 में उन्हें 'प्रफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस' कनाडा में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया और उन्हें 'मर्क एवार्ड' से भी सम्मानित किया गया।
6. इसके पश्चात सन् 1960 में डॉ. खुराना अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एन्जाइम रिसर्च में प्रफेसर पद पर नियुक्त हुए। सन 1966 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर ली।
7. सन 1970 में डॉ. खुराना मैसचुसट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी (एम.आई.टी.) में रसायन और जीव विज्ञान के अल्फ्रेड स्लोअन प्रोफेसर नियुक्त हुए। तब से लेकर सन 2007 वे इस संस्थान से जुड़े रहे और बहुत ख्याति अर्जित की।
8. डॉ. खुराना ने जीन इंजिनियरिंग (बायॉ टेक्नॉलजी) विषय की बुनियाद रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेनेटिक कोड की भाषा समझने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका प्रतिपादित करने के लिए सन 1968 में डॉ. खुराना

बिल से जुड़ी ये प्रमुख चिंताएं

1. इस बिल के विरोध में विपक्ष का तर्क है कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि इससे सरकार नागरिकों की गोपनीय जानकारी अपने पास रखना चाहती है।
2. विपक्ष का यह भी तर्क है कि गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए कोई सुरक्षित पैमाने तैयार नहीं किए गए हैं, इससे डेटा का दुरुपयोग भी हो सकता है।

- को चिकित्सा विज्ञान का नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉ. हरगोविंद खुराना नोबल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति थे।
9. यह पुरस्कार उन्हें दो और अमेरिकी वैज्ञानिकों डॉ. राबर्ट होले और डॉ. मार्शल निरेनबर्ग के साथ सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया था। इन तीनों ने डी.एन.ए. अणु की संरचना को स्पष्ट किया था और यह भी बताया था कि डी.एन.ए. प्रोटीन्स का संश्लेषण किस प्रकार करता है।
10. नोबल पुरस्कार के बाद अमेरिका ने उन्हें 'नैशनल अकेडमी ऑफ साइंस' की सदस्यता प्रदान की

राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने की मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2017-2018 से 2019-2020 की अवधि के लिए **राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने की मंजूरी** दे दी है। ईएफसी के अनुमोदन के अनुरूप इसके लिए 1160 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। **12वीं पंचवर्षीय योजना** के दौरान वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के परामर्श से **योजना को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया** चलाई गयी। इसके तहत **8 योजनाओं** को उप-योजनाओं के रूप में राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के अधीन कर दिया गया है। इसके कारण योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिली। इसके अलावा योजनाओं की कुशलता में सुधार आया और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बेहतर नतीजे प्राप्त हुए। योजना के लाभार्थियों में 15-29 वर्ष आयु समूह के युवा शामिल हैं जो राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 में 'युवा' की परिभाषा के अनुरूप है। विशेष रूप से किशोरों से संबंधित कार्यक्रम के घटकों के मामले में आयु समूह 10-19 वर्ष है।

पृष्ठभूमि

1. राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना, युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना है और यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय से चल रही है।
2. योजना का उद्देश्य युवाओं में व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों का विकास करना तथा युवाओं को राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में संलग्न करना है।

राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित 8 उप-योजनायें हैं-

1. नेहरू युवा केन्द्र संगठन
2. राष्ट्रीय युवा वाहिनी
3. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम
4. अंतरराष्ट्रीय सहयोग
5. युवा छात्रावास
6. स्काउट और गाइड संगठनों को सहायता
7. राष्ट्रीय अनुशासन योजना
8. राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम

सीओपी 24 के लिए कार्योंत्तर स्वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2-15 दिसंबर, 2018 तक कातोविसे, पोलैंड में आयोजित **यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी)** के बारे में **24वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी)** के दौरान भारत के दृष्टिकोण के बारे में बातचीत करने के लिए कार्योंत्तर मंजूरी प्रदान की है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। **इस बैठक में पोस्ट- 2020 अवधि** के दौरान **पेरिस समझौते को लागू करने के लिए दिशा-निर्देशों** को अंतिम रूप देने के बारे में ध्यान केन्द्रित किया गया था। भारत का दृष्टिकोण यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों और प्रावधानों से निर्देशित था। **इसमें इक्विटी और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमता के सिद्धांतों** (सीबीपीआर-आरसी) पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।

क्या है

1. भारत ने पेरिस समझौते के बारे में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और सामूहिक रूप से पेरिस समझौता लागू करने के लिए अपने वायदों को शामिल करते हुए सीओपी-24 के दौरान अपने नेतृत्व के बारे में प्रकाश डाला।
2. पर्यावरण सुरक्षा के बारे में अपने परम्परागत स्वभाव के अनुरूप भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन की चिंताओं से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
3. ये प्रयास जलवायु कार्रवाई की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सौर ऊर्जा से प्राप्त 24 गीगावाट बिजली क्षमता सहित 74 गीगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को अर्जित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को गति प्रदान की गई है।
4. इससे अंतर्राष्ट्रीय सौर समझौता, ऊर्जा दक्षता प्रयासों जैसे उदाहरणों के माध्यम से इसे सोलर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के अपने उद्देश्य से विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
5. यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि विकासशील देशों की कार्रवाई को वित्त, क्षमता निर्माण और विकसित देशों के तकनीकी समर्थन सहित सतत और पर्याप्त साधनों से मदद मिली है।
6. विकासशील देशों को समझौता लागू करने के साधन उपलब्ध कराने तथा विकसित देशों को जलवायु वित्त के निर्धारित स्तरों के बारे में स्पष्टता लाने के लिए विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विकसित देशों की बाध्यता को अपनाया गया मार्गदर्शन ही संचालित करता है।
7. सभी पक्ष अमेरिका के 100 बिलियन डॉलर से नए सामूहिक वित्तीय पोस्ट- 2020 लक्ष्य को स्थापित करने के लिए कार्य शुरू करने पर सहमत थे।
8. कुल मिलाकर भारत के दीर्घकालिक हितों की सुरक्षा की गई। भारत ने जीएसटी प्रक्रिया के उत्पादन में इक्विटी पर सोच-विचार की जरूरत के संबंध में ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी) निर्णय के बारे में अमेरिका की शंका को व्यक्त किया है।
9. यह गरीबों और सीमांत लोगों की कमजोरियों, समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए पेरिस समझौते के आदेश के अनुसार जीएसटी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मॉनसेंटो को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट से बहुराष्ट्रीय कंपनी मॉनसेंटो को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आनुवांशिक रूप से संबद्धित कपास के बीजों (जीएम कॉटन सीड्स) पर कंपनी के पेटेंट के दावे को जायज ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि अमेरिकी बीज निर्माता कंपनी जीएम (जीन संबद्धित) कॉटन सीड्स पर पेटेंट का दावा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसकी वजह से मॉनसेंटो जीएम कॉटन सीड्स पर पेटेंट का दावा नहीं कर पा रही थी। मॉनसेंटो को जर्मनी की दवा और फसलों के लिए रासायन बनाने वाली कंपनी बेयर एजी खरीद चुकी है। कोर्ट के इस फैसले को विदेशी कृषि कंपनियों मसलन मॉनसेंटो, बेयर, डूपा पायोनियर और सेनजेटा के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इन कंपनियों को भी भारत में जीएम फसलों पर पेटेंट के हाथ से जाने का डर सता रहा था।

क्या है

1. मेको मॉनसेंटो बायोटेक (इंडिया), मॉनसेंटो और महाराष्ट्र की हाइब्रिड सीड कंपनी (मेको) का संयुक्त उपक्रम है और यही कंपनी 40 से अधिक भारतीय बीज कंपनियों को जीएस कॉटन बीज की बिक्री करती है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला स्थानीय कंपनी एनएसएल की याचिका पर आया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत का पेटेंट कानून मॉनसेंटो को उसके जीएम कॉटन बीज पर किसी तरह के पेटेंट की इजाजत नहीं देता है।
2. इसके बाद मॉनसेंटो के भारतीय साझा उपक्रम (जेवी) ने रॉयल्टी भुगतान के विवाद को लेकर 2015 में एनएसएल के साथ अपने करार को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2018 को कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट को मॉनसेंटो के उस दावे को भी देखना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनएसएल ने बीटी कॉटन सीड्स को लेकर उसकी बौद्धिक संपदा का उल्लंघन किया है।

3. 2003 में मॉनसेंटो के जीएम कॉटन सीड को मंजूरी दी गई थी। भारत दुनिया में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। इसके साथ ही वह कपास का दूसरा बड़ा निर्यातक है। भारत में कपास की खेती का 90 फीसद रकबा, मॉनसेंटो की जीएम बीज पर निर्भर है।

दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिकों में भारत के महज 10

भारत में कई प्रख्यात साइंस और सोशल साइंस इस्टिच्यूट हैं, जैसे आईआईएससी, आईआईटी, टीआईएफआर, जेएनयू और टीआईएसएस। इसके बाद भी दुनिया के बेहतरीन एक प्रतिशत रिसर्चर्स की लिस्ट में भारत के महज 10 लोग ही अपना नाम दर्ज करा सके हैं। यहां तक कि इनमें से भी कुछ देश के टॉप इंडिस्ट्रियल से नहीं हैं। क्लैरिफेट एनालिटिक्स द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावी 4000 रिसर्चर्स एक लिस्ट जारी की गई है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पीएम की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के पूर्व प्रमुख सीएनआर राव को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। लिस्ट में 80 प्रतिशत नाम सिर्फ 10 देशों से हैं। वहीं 70 प्रतिशत नाम सिर्फ 5 देशों से हैं। इस्टिच्यूट की बात करें तो लिस्ट में 186 नाम ऐसे हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं।

क्या है

1. जहां भारत का प्रतिनिधित्व बेहद कम है, वहीं लिस्ट में 482 नाम के साथ चीन तीसरे नंबर पर है। 2,639 नाम के साथ अमेरिका टॉप पर है, वहीं 546 नामों के साथ यूके दूसरे नंबर पर है।
2. जेएनयू के दिनेश मोहन, जिनका नाम इस लिस्ट में है, ने कहा कि पिछले साल तक इस लिस्ट में 5 से भी कम नाम भारत से थे। उन्होंने कहा, इस साल उन्होंने क्रॉस फील्ड नाम की एक और कैटिगरी शामिल की है, जिसके बाद ये नाम आगे हैं।
3. करीब 15 साल पहले, भारत और चीन एक स्तर पर थे। लेकिन चीन दुनिया भर के विज्ञान में 15-16 प्रतिशत भागीदारी करता है, वहीं भारत सिर्फ 3-4 प्रतिशत करता है।
4. आईआईटी कानपुर के प्रफेसर अविनाश अग्रवाल का नाम भी इस लिस्ट में है ने कहा कि अप्लाइड रिसर्च को भारत जैसे देशों में ज्यादा महत्व नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि हमें अपना रिसर्च इकोसिस्टम बेहतर करने की जरूरत है।
5. इस लिस्ट में एनआईटी भोपाल के अलोक मिश्र और ज्योति मिश्र (आलोक और ज्योति पति-पत्नी हैं, लिस्ट में ज्योति अकेली महिला रिसर्चर हैं), आईआईटी मद्रास के रजनीश कुमार, इस्टिच्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर के संजीव साहू, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट रिसर्च इस्टिच्यूट के राजीव वाष्णोय और कोयंबटूर की भारतियार यूनिवर्सिटी के सक्थिवेल राथिनास्वामी का नाम शामिल है।

106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में उद्घाटन व्याख्यान दिया। इस कांग्रेस की विषयवस्तु 'भावी भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी' का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की असली ताकत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को लोगों के साथ जोड़ने में है। प्रधानमंत्री ने अतीत के महान वैज्ञानिकों जेसी बोस, सीवी रमण, मेघनाद साहा और एसएम बोस जैसे आचार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन लोगों ने 'न्यूनतम संसाधन' और 'अधिकतम प्रयास' के जरिए जनता की सेवा की। प्रधानमंत्री ने कहा, "सैकड़ों भारतीय वैज्ञानिकों का जीवन और कार्य प्रौद्योगिकी विकास और राष्ट्र निर्माण के संबंध में उनके गहरे बुनियादी दृष्टिकोण की समग्रता का परिचायक है। हमारे विज्ञान के आधुनिक मंदिरों के माध्यम से भारत अपने वर्तमान को बदल रहा है और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का काम कर रहा है।"

क्या है

1. प्रधानमंत्री ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने 'जय जवान, जय किसान' नारा दिया, जबकि अटल जी ने इस नारे में 'जय विज्ञान'

- को जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम एक कदम आगे बढ़ें और इसमें जय अनुसंधान को संलग्न करें।
2. प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि विज्ञान का लक्ष्य दो उद्देश्यों को प्राप्त करने से पूरा होता है-सघन ज्ञान का सृजन और इस ज्ञान को सामाजिक-आर्थिक भलाई में लगाना।
 3. श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विज्ञान ईको-प्रणाली की खोज को बढ़ावा देने के साथ हमें नवाचार और स्टार्ट-अप पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने वैज्ञानिकों में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए अटल नवोन्मेष मिशन की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों की तुलना में पिछले 4 वर्षों के दौरान ज्यादा टेक्नॉलाजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स स्थापित किये गये।
 4. प्रधानमंत्री ने कहा कि बिग डाटा विश्लेषण, कृत्रिम बौद्धिकता, ब्लॉक-चेन इत्यादि को कृषि सेक्टर, विशेषकर छोटी जोत वाले किसानों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने 2018 में भारतीय विज्ञान की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

1. विमानों में इस्तेमाल करने योग्य जैव-ईंधन का उत्पादन
2. दिव्य नयन ख दृष्टि बाधितों के लिए मशीन
3. ग्रीवा का कैंसर, तपेदिक और डेंगू के निदान के लिए सस्ते उपकरण
4. सिक्किम-दार्जिलिंग क्षेत्र में वास्तविक समय में भूस्खलन चेतावनी प्रणाली

असम समझौते के खंड 6 के लिए उच्च स्तरीय समिति

सरकार ने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) अधिसूचित की है। समिति को व्यापक अधिदेश दिया गया है। इसके अध्यक्ष श्री एम.पी. बेजबरौआ हैं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित असमिया व्यक्ति इसमें शामिल हैं। समिति अधिसूचना की तारीख से 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। असम की राज्य सरकार समिति को आवश्यक प्रशासनिक और संधार-तंत्र सहायता प्रदान करेगी। एचएलसी का गठन 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, जिसे असम समझौता के नाम से जाना जाता है, के खंड 6 के अनुसार गठित किया गया है। समझौते के खंड 6 में कहा गया है कि: संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा, जैसा कि उचित हो सकता है, असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रदान किया जाएगा। एचएलसी को भारत सरकार के गृह मंत्रालय को पूर्वोत्तर प्रभाग द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी।

उच्च स्तरीय समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं:

1. श्री एम.पी. बेजबरौआ, भाप्रसे (सेवानिवृत्त) ख अध्यक्ष
2. श्री सुभाष दास, भाप्रसे (सेवानिवृत्त) ख सदस्य
3. डॉ. नागेन सैकिया- सदस्य, पूर्व अध्यक्ष, असम साहित्य सभा
4. श्री धीरेन बेजबरौआ, - सदस्य, द सेंटिनल के पूर्व संपादक
5. डॉ. मुकुंद राजबंशी, - सदस्य, शिक्षाशास्त्र
6. श्री रमेश बोरपात्रगोहिन, - सदस्य, महाधिवक्ता, असम
7. श्री रोंगबोंग टेरंग, - सदस्य, पूर्व अध्यक्ष, असम साहित्य सभा
8. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का एक प्रतिनिधि सदस्य
9. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य सचिव

समिति के लिए संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं

1. समिति असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए 1985 से अब तक की गई कार्रवाइयों की प्रभावशीलता की जांच करेगी।
2. समिति विभिन्न संगठनों, सामाजिक संगठनों, कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों, कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संरक्षणवादियों, अर्थशास्त्रियों, भाषाविदों और समाजशास्त्रियों के साथ विचार-विमर्श करेगी।

3. समिति असमिया लोगों के लिए असम विधानसभा और स्थानीय निकाय में सीटों के आरक्षण के उपयुक्त स्तर का आकलन करेगी।
4. समिति असमिया और असम की अन्य स्थानीय भाषाओं की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों का भी सुझाव देगी।
5. समिति असमिया लोगों के लिए असम सरकार के तहत रोजगार में आरक्षण के उचित स्तर की सिफारिश करेगी।
6. समिति असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक अन्य उपाय सुझा सकती है।

“वेब वंडर वुमन” अभियान लांच

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन अभियान #www - Web- WonderWomen लांच किया है। इस अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं को खोजना और उनके असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देना है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सार्थक एजेंडा चला रही हैं। इस अवसर पर केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी तथा ट्वीटर की ग्लोबल हेड, पब्लिक पॉलिसी श्री कॉलिन क्रोवेल तथा ब्रेकथ्रू की अध्यक्ष और सीईओ सुश्री सोहिनी भट्टाचार्य उपस्थित थीं।

क्या है

1. इस अभियान के माध्यम से मंत्रालय तथा अभियान के साझेदार का उद्देश्य विश्व की भारतीय महिला दिग्गजों की दृढ़ता को मान्यता देना है, जिन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सार्थक अभियान चलाया है। यह अभियान इन मेधावी महिलाओं के प्रयासों को मान्यता देगा।
2. इस अवसर पर केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने कहा कि भारतीय महिलाएं हमेशा से उद्यमी रही हैं और उन्होंने अपने कठिन परिश्रम, अनुभव तथा ज्ञान के बल पर समाज पर सार्थक प्रभाव डाला है।
3. ऑनलाइन #www : Web- WonderWomen' अभियान का उद्देश्य ऐसे स्वरों को सम्मान और प्रोत्साहन देना है, जिन्होंने सोशल मीडिया मंचों पर सार्थक प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय ब्रेकथ्रू तथा ट्वीटर इंडिया के साथ साझेदारी से प्रसन्न है।
4. इस अभियान में निर्धारित मानक के अनुसार पूरे विश्व से नामांकन के माध्यम से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। नामांकन 31 जनवरी, 2019 तक होगा। विश्व में कहीं भी कार्य कर रही या बसी हुई भारतीय मूल की महिलाएं नामांकन की पात्र हैं।
5. चयनित प्रविष्टियों को ट्वीटर पर सार्वजनिक वोटिंग के लिए खोला जाएगा और निर्णायकों के पैनल द्वारा फाइनल में पहुंचने वालों का चयन किया जाएगा। स्वास्थ्य, मीडिया, साहित्य कला, खेल, पर्यावरण संरक्षण और फैशन सहित अनेक श्रेणियों में नामांकन आमंत्रित किए गए हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मे समझौता

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यू मह डी) ने भवन ऊर्जा दक्षता में सहयोग का शुभारंभ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार बीई और सीपीडब्ल्यूशुभ डी ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) अनुवर्ती नई इमारतों के डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देने तथा बिना पंजीकरण या नवीकरण शुल्को के पूरे देश में सीपीडब्ल्यू डी द्वारा प्रबंध की जा रही इमारतों की स्टाशर रेटिंग, भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के बारे में जागरूकता फैलाने तथा ईसीबीसी में सीपीडब्ल्यू डी पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण में सहयोग करेंगे।

क्या है

1. यह समझौता ज्ञापन पांच वर्ष तक लागू रहेगा जब तक कोई पक्ष उसे रद्द नहीं कर देता। विद्युत मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है जिसके ऊपर ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में नीति और कार्यक्रमों को लागू करने का दायित्व है, जबकि सीपीडब्ल्यू डी भारत सरकार की एक प्रमुख निर्माण एजेंसी है।

2. इनका यह संघ देश में ऊर्जा दक्षता भवनों के लिए नए मानदंड स्थापित करेगा और भारत सरकार के ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को अर्जित करने के दृष्टिकोण में मदद करेगा।
3. इस समझौता ज्ञापन पर बीईई के महानिदेशक श्री अभय बाकरे और सीपीडब्ल्यू कर डी के महानिदेशक श्री प्रभाकर सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर भारत सरकार के विद्युत सचिव श्री अजय कुमार भल्लो और विद्युत मंत्रालय, बीईई तथा सीपीडब्ल्यू डी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
4. अभी हाल में 14 दिसंबर, 2018 को आवासीय क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए आवासीय भवनों के लिए एक ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ईसीओ निवास संहिता 2018 की शुरूआत की गई है।
5. इस कोड का उद्देश्य अपार्टमेंट्स और टाउनशिप सहित घरों के निर्माण और डिजाइन को बढ़ावा देना है ताकि इनमें रहने वालों को ऊर्जा दक्षता के लाभ प्राप्त हो। 2017 के दौरान भारत सरकार ने वाणिज्यिक भवनों के लिए ईसीबीसी 2017 के अद्यतन संस्करण की शुरूआत की थी।

अन्तरराष्ट्रीय

भारत ने चाबहार का प्रचलन शुरू किया

भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2018 को चाबहार त्रिपक्षीय समझौता बैठक के दौरान ईरान में शाहिद बेहश्ती बन्दरगाह, चाबहार के एक भाग के प्रचलन का दायित्व ग्रहण कर लिया। चाबहार स्थित भारतीय एसपीवी ख इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन (आईपीजीसीएफजेड) के कार्यालय का भारत, ईरान और अफगानिस्तान के शिष्टमंडलों के प्रमुखों ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। टर्मिनल एरिया, कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट और कार्यालय की इमारत को वास्तविक रूप से नियंत्रण में लेने का कार्य 29 दिसंबर 2018 तक पूरा हो जाएगा।

क्या है

1. आईपीजीसीएफजेड में वाणिज्यिक प्रचालन एक पोत के आगमन के साथ ही आरंभ हो गया। साइप्रस में पंजीकृत यह पोत 72458 एमटी मक्का के नौभार के साथ चाबहार पहुंचा।
2. पोत एमवी मेचेराज ने 30 दिसंबर 2018 को 0130 बजे टर्मिनल पर लंगर डाला। आईपीजीसीएफजेड ने नुमैटिक अन-लोडर्स का इस्तेमाल करते हुए आयतित नौभार (एक्स ब्राजील) को डिस्चार्ज कर अपने प्रथम कार्गो प्रचालन को कार्यान्वित किया।
3. इसके साथ ही एक लंबी यात्रा की शुरूआत हो गई। चाबहार के साथ संबंध जोड़कर भारत ने इतिहास रच दिया और अब वह चारों तरफ से जमीन से घिरे अफगानिस्तान की सहायता के लिए क्षेत्रीय सहयोग और साझा प्रयासों की अगुवाई कर रहा है। भारत द्वारा अपने भू-भाग से बाहर किसी बंदरगाह के प्रचालन का यह पहला मौका है।
4. भारत ने चाबहार बन्दरगाह के बारे में ईरान के साथ 2003 के आसपास बातचीत शुरू की थी, लेकिन इसे महत्वपूर्ण बल 2014 की आखिरी छिमाही में मिला, जिसके परिणामस्वरूप चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए मई 2015 में दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।
5. इस एमओयू को चाबहार बंदरगाह को उपकरणों से लैस करने और उसका प्रचालन करने के लिए 10 साल के औपचारिक समझौते में परिवर्तित किया गया, जिसे 23 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान निष्पामदित किया गया।

भारत और पाकिस्तान ने साझा की परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची

भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों और एक-दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची साझा की। विदेश मंत्रालय ने 1 जनवरी 2018 को एक बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने 347 कैदियों की सूची पाकिस्तान से साझा की है। इनमें 98 मछुआरे और 249 अन्य कैदी शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपनी जेलों में बंद 537 भारतीय कैदियों की सूची साझा की है। इनमें 483 मछुआरे और 54 अन्य लोग शामिल हैं। सरकार ने नागरिक कैदियों, गुमशुदा भारतीय रक्षा कर्मियों, मछुआरों एवं नौकाओं को जल्द छोड़ने को कहा है। इस संदर्भ में उन 17

भारतीय नागरिक कैदियों एवं 369 मछुआरों को रिहा करने में तेजी लाने को कहा गया है जिनकी नागरिकता की पुष्टि हो चुकी है। पाकिस्तान से उनके 80 कैदियों के मामले में जल्द प्रतिक्रिया देने को भी कहा गया है जिन्होंने अपनी सजा पूरा कर ली है।

क्या है

1. भारत और पाकिस्तान के बीच 21 मई, 2008 को हुए राजनयिक पहुंच संबंधी समझौते के तहत यह कदम उठाया गया।
2. इसके तहत दोनों देशों को कैदियों की सूची एक साल में दो बार- एक जनवरी और एक जुलाई को साझा करनी होती है। दोनों देश बार-बार तनाव के बावजूद कैदियों की सूची साझा करने की परंपरा का पालन करते रहे हैं।
3. भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची भी साझा की। दोनों देशों के बीच 31 दिसंबर, 1988 को परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले पर प्रतिबंध संबंधी समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देश अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं।

नए साल पर यूनिसेफ की रिपोर्ट

नए साल के पहले ही दिन भारत में 69,944 नवजातों का जन्म हुआ। यह संख्या दुनिया में सर्वाधिक है। भारत के बाद चीन का नंबर रहा, जहां 44,940 नवजात दुनिया में आए। संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष (यूनिसेफ) की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। नाइजीरिया में 1 जनवरी, 2019 को 25,685 बच्चों के जन्म लेने की जानकारी दी गई है। 2019 में बाल अधिकार संधि की 30 वीं सालगिरह भी होगी, जिसे यूनिसेफ विश्वभर में कार्यक्रम आयोजित कर मनाएगा। इस संधि के तहत सरकारें प्रत्येक बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य सेवा व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति वचनबद्ध है। यूनिसेफ के डिप्टी कार्यकारी निदेशक पेट्री गोरनित्जका ने कहा, 'नए साल के पहले दिन हम सब संकल्प लें कि प्रत्येक बच्चे के जीने के अधिकार का संरक्षण हो। यदि हम स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण व उन्हें सशक्त बनाने में निवेश करें तो प्रत्येक नवजात का जन्म सुरक्षित हाथों में हो सकता है।

क्या है

1. साल के पहले दिन एक जनवरी को भले विश्व में करीब चार लाख बच्चों का जन्म हुआ हो। हजारों अलेक्जेंडर, आयशा, राधा, कृष्ण, राम और रहीम जन्मे मगर हकीकत यह भी है कि लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका नामकरण का मौका ही नहीं आता। वे एक दिन भी जी नहीं पाते हैं।
2. यूनिसेफ के अनुसार 2017 में करीब 10 लाख बच्चे जन्म के पहले दिन ही काल कवलित हो गए थे और करीब 25 लाख ने जन्म के पहले माह में दम तोड़ दिया था।
3. इन बच्चों में अधिकांश की मौत समय पूर्व जन्म, प्रसूति के दौरान आकस्मिक घटना, संक्रमण, निमोनिया जैसे टाले जा सकने वाले कारणों की वजह से हुई थीं। इससे उनके जीने के मूलभूत अधिकार का हनन हुआ।

कहां कितने बच्चों का जन्म

1. 3,95,072 बच्चे विश्व भर में जन्मे
2. 98,768 बच्चे दक्षिण एशिया में
3. 15,112 बच्चे पाकिस्तान में
4. 8,428 का जन्म बांग्लादेश में
5. 18 फीसद बच्चे भारत में जन्मे

ताशकंद समझौता

ताशकंद समझौते (The Tashkent Declaration) की चर्चा शुरू होते ही बरबस लाल बहादुर शास्त्री जी की यादें ताजा हो जाती हैं। यह समझौता भारत-पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था। भारत-पाकिस्तान के युद्ध के बाद इस समझौते की जरूरत महसूस की गई थी। सोवियत संघ के ताशकंद में 10 जनवरी, 1966 में भारत और पाकिस्तान ने

एक समझौते पर दस्ताखत किए। उस रात ताशकंद गए भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। 1965 के भारत-पाक युद्ध विराम के बाद उन्होंने कहा था कि हमने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, अब हमें शांति के लिए पूरी ताकत लगानी है। मरणोपरांत 1966 में उन्हें भारत के सर्वोच्च अलंकरण 'भारत रत्न' से विभूषित किया गया। **राष्ट्र के विजयी प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी समाधि का नाम भी विजय घाट रखा गया।**

क्या है ताशकंद समझौता

1. ताशकंद **सम्मेलन** सोवियत रूस के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किया गया था। यह ताशकंद समझौता संयुक्त रूप से प्रकाशित हुआ था।
2. ताशकंद समझौता (जेम जैमदज कमबसंतजपवद) भारत-पाकिस्तान के बीच को हुआ एक शांति समझौता था। इसमें यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी-अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे।
3. 25 फरवरी 1966 तक दोनों **देश अपनी सेनाएं सीमा रेखा से पीछे हटा** लेंगे। दोनों देशों के बीच आपसी हितों के मामलों में शिखर वार्ताएं तथा अन्य स्तरों पर वार्ताएं जारी रहेंगी।
4. भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच हुए ताशकंद समझौता के तहत दोनों देशों को जीती हुई भूमि लौटानी पड़ी। यह करार का अहम हिस्सा था।
5. भारत और पाकिस्तान शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने-अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण समाधान खोजेंगे। **दोनों देश** 25 फरवरी, 1966 तक अपनी सेना 5 अगस्त, 1965 की सीमा रेखा पर पीछे हटा लेंगे।
6. इन दोनों देशों के बीच आपसी हित के मामलों में शिखर वार्ता तथा अन्य स्तरों पर वार्ता जारी रहेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आधारित होंगे।
7. दोनों **देशों के बीच** राजनयिक संबंध फिर से **स्थापित** कर दिए जाएंगे। एक-दूसरे के बीच में प्रचार के कार्य को फिर से सुचारू कर दिया जाएगा।
8. आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों तथा संचार संबंधों की फिर से स्थापना तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान फिर से शुरू करने पर विचार किया जाएगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएंगी कि लोगों का निर्गमन बंद हो।
9. शरणार्थियों की समस्याओं तथा अवैध प्रवासी प्रश्न पर विचार-विमर्श जारी रखा जाएगा तथा हाल के संघर्ष में जब्त की गई एक दूसरे की संपत्ति को लौटाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।
10. **भारत-पाक के बीच संबंध एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आधारित होंगे।** दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे।
11. ताशकंद समझौते के बाद पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही हृदयगति रुक जाने से निधन हो गया।

69 वर्षों में चार बार बदला इस देश का नाम

11 जनवरी, 1972 को जब भारतीय सेना पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में जीत का जश्न और उल्लास मना रही थी, उस वक्तज पड़ोस में **एक नवोदित राष्ट्र का उदय** हुआ। इस नवोदित राष्ट्र का नाम बांग्लादेश है। हालांकि, प्रतिवर्ष 26 मार्च को बांग्ला देश अपना स्वतंत्रता दिवस मानता है, लेकिन 11 जनवरी, 1972 को इस देश का नामकरण हुआ। इस दिन पूर्वी पाकिस्तान नया राष्ट्र बांग्लादेश बन गया। इसलिए 11 जनवरी का दिन बांग्लादेश के लिए काफी अहम है। आइए जानते हैं बांग्लादेश की राजनीतिक, भौगोलिक और इसके सामाजिक इतिहास के बारे में। आखिर बंगाल, पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तानी से कैसे बन गया बांग्लादेश।

क्या है

1. **भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद इसे पूर्वी बंगाल नाम दिया गया।** इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान और आजादी के बाद यह बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।

2. यहां के प्रारंभिक सभ्यता में बौद्ध और हिंदू धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। यहां के स्थापत्यक और कला में ऐसे तमाम अवशेष हैं जिसे मंदिर या मठ कहा जा सकता है।
3. बंगाल के इस्लामीकरण का दौर 13वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के व्यापारियों के साथ शुरू हुआ। इसके बाद यहां इस्लाम का वर्चस्व रहा। यूरोप के व्यापारियों का यहां आगमन करीब 15वीं शताब्दी में हुआ।
4. 18वीं शताब्दी के शुरुआत में यह क्षेत्र पूरी तरह से ईस्टर इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। स्वाधीनता के बाद भारत को हिंदू बहुल भारत और पाकिस्तान को मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में विभाजित करना पड़ा।
5. दरअसल, पाकिस्तान के गठन के समय पश्चिमी क्षेत्र में सिंधी, पठान, बलोच और मुजाहिरों की बड़ी संख्या थी, जबकि पूर्व हिस्से में बंगाली बोलने वालों का बहुमत था।
6. 1970 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में पूर्वी क्षेत्र में शेख की पार्टी आवामी लीग ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। शेख की पार्टी का पाकिस्तानी संसद में बहुमत हासिल किया। वह पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के दावेदार थे।
7. **भारत-पाकिस्तान के विभाजन के बाद बंगाल** के दो हिस्से हो गए। हिंदू बहुल इलाके को पश्चिम बंगाल और मुस्लिम बहुल इलाके को पूर्वी बंगाल नाम दिया गया।
8. 1950 में यहां जमींदारी प्रथा के खिलाफ और 1952 में बांग्ला भाषा के आंदोलन ने पाकिस्तान सरकार को झकझोर कर रख दिया। 1955 में पाकिस्तानी हुकूमत ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान हुकूमत का यह कदम पूर्वी बंगाल के लोगों को आहत करने वाला था।

तिथियों में बांग्लादेश

1. 1947 : भारत के विभाजन के बाद बंगाल से कटकर पूर्वी बंगाल अस्तित्व में आया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान अस्तित्व में आया।
2. 1949 : आवामी लीग की स्थापना हुई। इसका मकसद पूर्वी पाकिस्तान को आजादी दिलाना था।
3. 1966 : आवामी लीग ने छह बिंदुओं को लेकर आंदोलन की घोषणा।
4. 1970 : शेख मुजीब के नेतृत्व में आवामी लीग ने चुनाव में भारी जीत हासिल हुई। पाकिस्तानी हुकूमत ने परिणाम मानने से इंकार किया। शेख को जेल भेजा गया। सरकार के इस फैसले के बाद पूर्वी पाकिस्तान में बगावत।
5. 1971 : शेख मुजीब की आवामी लीग ने 26 मार्च को स्वतंत्रता का ऐलान किया। पाकिस्तान सेना की जुल्म से बचने के लिए करीब एक करोड़ लोग भारत में शरण लेने के लिए पहुंचे।
6. 1972 : नए देश का नाम बांग्लादेश रखा गया। शेख मुजीब प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का अभियान चलाया लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं मिली।
7. 1974 : देश में भीषण बाढ़ से पूरी फसल तबाह 28,000 लोग की मौत। देश में आपात स्थिति, राजनीतिक गड़बड़ियों की शुरुआत।
8. 1975 : शेख मुजीब बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। अगस्त में हुए सैनिक तख्ता पलट के बाद उनकी हत्या कर दी गई, देश में सैनिक शासन लागू हो गया।
9. 1977 : जनरल जिया-उर-रहमान राष्ट्रपति बने। इस्लाम को सांविधानिक मान्यता दी गई।
10. 1979 : देश में चुनाव हुए और सैनिक शासन समाप्त हुआ। जनरल जिया-उर-रहमान की बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने बहुमत हासिल किया।

भारत और डेनमार्क के बीच समुद्रीय मुद्दों पर समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डेनमार्क में समुद्रीय मुद्दों के बारे में समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी है। समझौता ज्ञापन पर डेनमार्क के डब्ल्यूभारतआईपी की जनवरी 2019 में होने वाली भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया गया है।

क्या है

1. इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने का मार्ग प्रशस्त होगा :
2. भारत और डेनमार्क के समुद्रीय क्षेत्रों के मध्यस सीमा पार सहयोग और निवेशों में मदद करना;
3. यह दोनों देशों को गुणवत्तीपूर्ण शिपिंग सुनिश्चित करने के लिए आपसी क्षमताओं को सुधारने के लिए विशेषज्ञों, प्रकाशनों, सूचना, डाटा और सांख्यिकी का आदान-प्रदान करने, हरित समुद्रीय प्रौद्योगिकी एवं शिपबिल्डिंग के क्षेत्र में सहयोग, भारत के शिपिंग पंजीयक को मान्यता प्राप्त संगठन (आरओ) का दर्जा प्रदान करने तथा समुद्रीय प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने में समर्थ बनाएगा;
4. मर्चेण्ट शिपिंग और समुद्रीय परिवहन संबंधित मामलों के क्षेत्र में सतत सहयोग के लिए अनुसंधान और विकास;
5. यह द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर दोनों देशों के लिए आपसी लाभ के अवसरों के बारे में सहयोग को आगे बढ़ाएगा और मजबूत बनाएगा।

पृष्ठभूमि

1. डेनमार्क भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों में से एक है। डेनमार्क से भारत को होने वाले प्रमुख आयातों में औषधीय/फार्मास्यूटिकल वस्तुएं, विद्युत उत्पादन मशीनरी, औद्योगिक मशीनरी, धातु खनिज, ऑर्गेनिक रसायन आदि शामिल हैं।
2. भारत से डेनमार्क को होने वाले निर्यात में सिलेसिलाए कपड़े, वस्त्र/फेब्रिक यार्न, सड़क वाहन और घटक, धातु की वस्तुएं, लोहा और स्टील, जूते और यात्रा वस्तुएं शामिल हैं।
3. दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और समुद्रीय क्षेत्र में सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए डेनमार्क के साथ द्विपक्षीय समझौता करने का प्रस्ताव किया गया है।

अमेरिका में देश का सबसे लंबा शटडाउन

मेक्सिको सीमा पर दीवार खड़ी करने के मुद्दे पर डेमोक्रेट्स से राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ठन जाने के बाद से पैदा हुआ सरकारी शटडाउन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बताया जा रहा है कि यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है जिसमें आठ लाख सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना पड़ रहा है।

क्या है

1. वॉल प्रॉजेक्ट के लिए ट्रंप के 5.7 अरब डॉलर की मांग को डेमोक्रेट्स द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद देश में कामकाज ठप हो गया है, क्योंकि जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप विभिन्न सरकारी विभागों के लिए बजट को मंजूरी नहीं दे रहे।
2. इसके कारण एफबीआई, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और म्यूजियम स्टाफ को वेतन नहीं मिला। यह आंशिक शटडाउन देश का सबसे लंबा शटडाउन बन गया। इससे पहले 1995-96 में बिल क्लिंटन के कार्यकाल में शटडाउन 21 दिनों तक चला था।
3. ट्रंप ने आपातकाल की घोषणा और बिना कांग्रेस की मंजूरी के फंड रिलीज करने की अपनी धमकी को वापस ले लिया है। उन्होंने वाइट हाउस में एक बैठक के दौरान कहा, 'मैं इसे इतनी जल्दी नहीं करने जा रहा।' ट्रंप ने हालांकि जोर दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार उनके पास है लेकिन साथ में यह भी कहा कि वह अब भी चाहते हैं कि कांग्रेस दीवार निर्माण के लिए कोष को मंजूरी दे।
4. उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने इससे पहले कहा था, 'अगर वे 5.7 अरब डॉलर की मंजूरी नहीं देते। मैं राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करूंगा, जिसका मेरे पास पूरा अधिकार है।'

कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने माना, सुश्रुत सर्जरी के जनक थे

प्राचीन भारतीय में नाक और प्लास्टिक सर्जरी की उत्पत्ति के बारे में सोचिए। मौजूदा समय में प्लास्टिक सर्जरी एक आधुनिक विलासिता है। यह पता चला है कि कॉस्मेटिक और शरीर की पुनर्संरचना की जड़े 2500 से अधिक वर्षों तक वापस चली जाती हैं। यह सामान्य धारणा है कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक एक कृत्रिम सामग्री को संदर्भित करता है, जब कि यह वास्तव में ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से निकलता है, जिसका अर्थ है ढालना या रूप देना।

क्या है

1. 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुए सुश्रुत नाम के एक भारतीय चिकित्सक को व्यापक रूप से सर्जरी का जनक माना जाता है। उन्होंने चिकित्सा और सर्जरी पर दुनिया के शुरुआती कार्यों में पहली बार विस्तार से लिखा। यही कारण है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने माना है कि सुश्रुत सर्जरी के जनक थे।
2. सुश्रुत संहिता में 1,100 से अधिक रोगों के बारे में जानकारी दी गई है। रोग प्रजनन में सैकड़ों औषधीय पौधों के उपयोग और सर्जिकल प्रक्रियाओं के बारे में निर्देश दिए गए थे जिसमें तीन प्रकार के त्वचा की कलम और नाक के पुनर्निर्माण शामिल हैं। त्वचा कलम में त्वचा के टुकड़ों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लगाया जाता है।
3. सुश्रुत का ग्रंथ माथे की लटकती हुई त्वचा के टुकड़े का प्रयोग नाक का संधान करने के लिए पहला लिखित रिकॉर्ड मिलता है। जिसमें एक तकनीक जो आज भी उपयोग की जाती है, जिसे माथे से त्वचा की पूरी मोटाई का टुकड़ा नाक को फिर से बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
4. उस समय उस प्रक्रिया की जरूरत वाले रोगियों में आम तौर पर वे लोग शामिल होते थे जो चोरी या व्यभिचार के लिए सजा के रूप में अपनी नाक खो चुके थे।
5. मौजूदा दौर में सर्जन आघात, संक्रमण, जलने के साथ-साथ ऊतकों की सुरक्षात्मक परतों को खोने वाले क्षेत्रों को बहाल करने के लिए त्वचा के कलम का उपयोग करते हैं साथ ही उन क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए जहां सर्जिकल हस्तक्षेप ने त्वचा को नुकसान हुआ है, जैसा कि मेलेनोमा (त्वचा संबंधी ट्यूमर) हटाने से हो सकता है। आश्चर्यजनक रूप से इन तकनीकों को सुश्रुत संहिता में विस्तार से समझाया गया है और दुनिया इससे प्रेरणा लेती है।
6. सुश्रुत संहिता में सर्जरी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताया गया है। इस किताब के अनुसार सुश्रुत शल्य चिकित्सा के किये 125 से अधिक स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग किया करते थे, जिनमें चाकू, सुइयां, चिमटियां की तरह ही थे, जो इनके द्वारा स्वयं खोजे गये थे। ऑपरेशन करने के 300 से अधिक तरीकों व प्रक्रियाएँ इस किताब में वर्णित हैं।
7. सुश्रुत संहिता में cosmetic surgery नेत्र चिकित्सा में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने में ये पूर्ण दक्ष थे तथा अपनी इस रचना में पूर्ण प्रयोग विधि भी लिखी है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन द्वारा प्रसव करवाना, टूटी हड्डियों का पता लगाकर उन्हें जोड़ना वे भली-भांति जानते थे। ये अपने समय के महान शरीर संरचना, काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग चिकित्सक थे।

अर्थशास्त्र

डिजिटल पेमेंट कमेटी का गठन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी की देखरेख में एक कमेटी का गठन किया है जो कि देश में डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और इसकी सुरक्षा को और मजबूत करने से जुड़े उपाय सुझाएगी। गौरतलब है कि नंदन नीलेकणी ने ही देश में हर व्यक्ति को आधार उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पांच सदस्यों वाली इस कमेटी का गठन डिजिटल

पेमेंट को बढ़ावा देने और डिजिटाइजेशन के जरिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें आगे कहा गया कि कमेटी को अपनी पहली बैठक के बाद अगले 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

क्या है

1. इस पैनल को देश में भुगतान के डिजिटलीकरण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने, इकोसिस्टम में मौजूदा गैप का पता लाने एवं उनको पाटने का सुझाव देने का काम सौंपा गया है और साथ ही इसे वित्तीय समावेशन में डिजिटल भुगतान के वर्तमान स्तरों का आकलन करने का भी जिम्मा दिया गया है।
2. वहीं कमेटी को डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदमों के बारे में भी जानकारी देनी है ताकि डिजिटल माध्यमों से वित्तीय सेवाओं को हासिल करने में ग्राहकों का विश्वास बढ़ सके। साथ ही इस कमेटी को दूसरे देशों में मौजूद व्यवस्थाओं का आकलन भी करना है।

कौन कौन है कमेटी का सदस्य?

1. इस कमेटी में नंदन नीलेकणी के अलावा अन्य सदस्यों में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एच आर खान, विजया बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ किशोर सनसी और आईटी व स्टील मंत्रालय में पूर्व सचिव अरुणा शर्मा और आईआईएम अहदाबाद में चीफ इनोवेशन ऑफिसर संजय जैन शामिल हैं।

कंपोजिशन स्कीम का दायर बढ़ा

जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि **कंपोजिशन स्कीम** की सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है। जो कारोबारी कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं उन्हें तिमाही आधार पर टैक्स का भुगतान करना होता है, लेकिन रिटर्न उन्हें साल में एक ही बार दाखिल करना होता है। इसके साथ ही केरल के लिए एक फीसद आपदा सेस को मंजूरी दी गई है।

क्या है

1. जीएसटी काउंसिल ने 10 जनवरी 2018 को **छोटे एवं मध्यम उद्योगों के लिए वस्तु एवं सेवाकर** की छूट सीमा को दोगुना कर दिया, जो कि एक अप्रैल 2019 से लागू होगी।
2. जीएसटी में टैक्स छूट की सीमा को कारोबारियों के लिए **20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख** कर दिया गया है। ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर एक साल में 4 मिलियन के आस पास होगा उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर को भी महीने भर के भीतर राहत मिल सकती है।
3. पिछले महीने सरकार **एकल राष्ट्रीय बिक्री कर** दर की दिशा में काम कर रही थी जो कि **12 से 18% के बीच** का हो सकता है। 1 जुलाई 2017 को जब वस्तु एवं सेवाकर को देशभर में लागू किया गया था तो वस्तुओं एवं सेवाओं को 5 फीसद से लेकर 28 फीसद की टैक्स स्लैब में रखा गया था।
4. जेटली ने कहा, **भविष्य में 12 और 18 फीसद** की दो मानक दरों के बजाए एक मानक दर को निर्धारित किया जा सकता है। यह इन दोनों के बीच की कोई मानक दर हो सकती है।
5. उन्होंने आगे कहा कि देश में **शून्य, पांच फीसद** और एक लगजरी एवं सिन गुड्स (शराब, ड्रग्स, सिगरेट, इत्यादि) के लिए एक मानक दर होनी चाहिए।

खुले भूमिक्षेत्र लाइसेंस कार्यक्रम का शुभारंभ

केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और कौशल विकास व उद्यमियता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नई दिल्ली में **खुला भूमिक्षेत्र लाइसेंस कार्यक्रम** (निविदा चरण-3) के लिए **एनआईओ और एमआरएससी** का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री एम.एम.कृष्णी और डीजीएच के महानिदेशक श्री वी.पी. जॉय भी उपस्थित थे। इस निविदा चरण में **लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के भूमिक्षेत्र में स्थित 14 ई एंड पी ब्लॉकों** के लिए निवेशक समुदाय से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। ये निविदाएं एचईएलपी के तहत आमंत्रित की गई हैं, जो निवेशक अनुकूल हैं। 10

ब्लॉक, निवेशकों द्वारा प्रस्तुत अभिव्यक्ति की रूचि पर आधारित है और चार ब्लॉकों को सरकार ने राष्ट्रीय भूकंप कार्यक्रम तथा संसाधन पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित किया है।

क्या है

1. इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि देश में ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ रही है और हम लोग ईंधन व परिवहन ईंधन की जरूरतों के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर हैं। ई एंड पी क्षेत्र एक चुनौती है और घरेलू उत्पादन बढ़ाने तथा अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई सुधार किये हैं।
2. ओएएलपी निविदा चरण-1 के तहत 60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का प्रस्ताव दिया गया था। दूसरे चरण में अतिरिक्त 30,000 वर्ग किलोमीटर के भूमिक्षेत्र का प्रस्ताव दिया गया है।
3. तीसरा चरण भी लगभग तैयार है। उन्होंने ने कहा कि पहले खोज का आधार सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व था, लेकिन इससे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अब सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है।
4. इस उद्देश्य के लिए आईओआर/ईओआर की घोषणा की गई है। उत्पादन वृद्धि संविदा प्रारूप पर भी काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने पर वित्तीय लाभ भी दिये जाएंगे और कठिन क्षेत्रों में विशेष लाभ देने की व्यवस्था की गई है।
5. भारत विश्व में ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और आने वाले वर्षों में देश में ऊर्जा खपत तेजी से बढ़ेगी। इस बढ़ती मांग को पूरा करने तथा ऊर्जा सुरक्षा व पर्याप्तता के संदर्भ में प्रधानमंत्री के विजन के आलोक में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण सुधार किये हैं।
6. नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के स्थालन पर हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) को मार्च, 2016 में मंजूरी दी गई थी।
7. राष्ट्रीय आंकड़ा भंडार (एनडीआर) के साथ खुला भूमिक्षेत्र लाइसेंस कार्यक्रम (ओएएलपी) को जून, 2017 में लांच किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) से संबंधित गतिविधियों को गति प्रदान करना था। इस कार्यक्रम के तहत 6 आवर्ती निविदा चरण शामिल किये गये हैं और इसकी शुरुआत 01 जुलाई, 2017 को की गई थी।
8. ओएएलपी के अंतर्गत पहला निविदा चरण जनवरी, 2018 को लांच किया गया था और यह चरण मई, 2018 में समाप्त हुआ। अक्टूबर, 2018 में 59,282 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल वाले 55 ब्लॉक प्रदान किये गये।
9. सरकार ओएएलपी निविदा चरण-3 को अंतिम रूप दे रही है और इसके तहत अगले कुछ सप्ताहों में 32,000 किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के लिए निविदाएं जारी की जाएंगी। सरकार ने अन्वेषण के रकबे में वृद्धि की है।
10. 2017 में अन्वेषण का रकबा लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर था, जो ओएएलपी-1 में बढ़कर 1,50,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। ओएएलपी-2 में यह रकबा बढ़कर 2,10,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। मई, 2019 तक चरण-3 के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 3,00,000 वर्ग किलोमीटर (2019 के अंत तक) हो जाने की संभावना है। 2019 में चरण-4 और चरण-5 को अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है।
11. एचईएलपी के तहत लाइसेंस कार्यक्रम से “व्याकरण करने में आसानी” बेहतर होगी, क्योंकि यह राजस्व साझा प्रारूप पर आधारित है। इसमें रॉयल्टी दरों को कम किया गया है, कोई तेल अधिभार नहीं है, मूल्य निर्धारण और विपणन की सुविधा है, पूरे वर्ष भर अभिरूचि की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रत्येक छह महीने में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं तथा पारंपरिक और गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बन संसाधनों के लिए एक ही लाइसेंस की व्यवस्था की गई है।
12. प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एनआईओ) के लांच होने के पश्चात् बोली लगाने वाले राष्ट्रीय आंकड़ा भंडार (एनडीआर) पर आंकड़ों का अध्ययन कर सकते हैं और निविदा के लिए ब्लॉक का चयन कर सकते हैं।
13. निविदा की बोली लगाने वाले अपनी निविदाएं 08 जनवरी, 2019 से शुरू होने वाले पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह निविदा चरण 12 मार्च, 2019 तक जारी रहेगी। ये ब्लॉक 7 बेसिनों में स्थित हैं। ओएएलपी-2 के अंतर्गत 8 ब्लॉक (भूमि), 5 ब्लॉक (समुद्र तट के निकट) और 01 ब्लॉक (गहरे समुद्र में) शामिल हैं। संभावना

है कि 500-600 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ ओएएलपी चरण-2 के तहत अन्वेषण का कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। (षण का कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा।

विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय को मंजूरी

कैबिनेट ने देना और विजया बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय को मंजूरी दे दी है। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने विजया बैंक और देना बैंक का खुद के साथ विलय के लिये शेयरों की अदला-बदली अनुपात को अंतिम रूप दे दिया।

क्या है

1. विलय की योजना के मुताबिक, **विजया बैंक के शेयरधारकों** को प्रत्येक 1,000 शेयरों के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 402 इक्विटी शेयर मिलेंगे।
2. वहीं देना बैंक के मामले में, उसके शेयरधारकों को प्रत्येक 1,000 शेयर के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 110 शेयर मिलेंगे।
3. सरकार ने पिछले साल सितंबर में विजय बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय की घोषणा की थी।
4. विलय के फलस्वरूप बनने वाली इकाई एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।

विदेशी काला धन कानून में खुलासा

सरकार की ओर से 2015 में लागू विदेशी काला धन कानून के तहत 6,000 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का पता चला है, संसद में इसकी जानकारी दी गई। इसके अलावा 31 अक्टूबर 2018 तक, विदेशी काला धन कानून के तहत 34 अभियोजन पक्ष की शिकायतें दर्ज की गई हैं। राज्य सभा में एक लिखित जवाब में राज्य वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, **काला धन** (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम 2015 के प्रभाव (काला धन अधिनियम) के तहत आयकर विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में 31 अक्टूबर 2018 तक 6000 करोड़ रुपये के अघोषित संपत्ति का पता लगाया गया है।

क्या है

1. इस अधिनियम के तहत ऐसे लोगों को एक बार मौका दिया गया था जिनके पास विदेशी संपत्ति है लेकिन वे आयकर से बचने के लिए अपनी संपत्ति छुपा रहे हैं।
2. 30 सितंबर 2015 को बंद हुई इस स्वीकृति में 4,100 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्ति से जुड़े 648 घोषणाएं की गईं। ऐसे मामलों में कर और जुर्माने के माध्यम से 2,470 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूली गई।
3. जिन लोगों के पास विदेशी संपत्ति और आय है उनके खिलाफ अधिनियम के तहत उपयुक्त कार्रवाई की गई है। इस तरह की कार्रवाइयों में पूछताछ, आय का आकलन, करों का लाभ, दंड और आपराधिक अदालतों में अभियोजन की शिकायतों को दाखिल करना शामिल है।

विज्ञान एवं तकनीकी

एम-2-एम/आईओटी पर सम्मेलन

केन्द्रीय संचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रेल राज्यमंत्री श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि मशीन से मशीन (एम-2-एम) संचार और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) में हमारे जीवन को बदलने की क्षमता है। ये तकनीकें **हमारे भौतिक संसार से संपर्क करने के तरीके** को पूरी तरह बदल सकती हैं। श्री सिन्हा ने **दूरसंचार इंजिनियरिंग केन्द्र** (पीईसी), नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक दिवसीय 'स्मार्ट आधारभूत संरचना को एम-2-एम/आईओटी सक्षम बनाना' सम्मेलन का उद्घाटन किया।

क्या है

1. इस अवसर पर **टीईसी** द्वारा तैयार की गयी दो तकनीकी रिपोर्टों को भी श्री मनोज सिन्हा ने जारी किया।

2. पहली रिपोर्ट का शीर्षक 'आईओटी/एम-2-एम सुरक्षा के लिए अनुशासन' और दूसरी रिपोर्ट का शीर्षक 'आईओटी/आईसीटी के साथ स्मार्ट नगरों की डिजाइन और योजना निर्माण' है।
3. एम-2-एम/आईओटी संचार के अंतर्गत उभरती हुई तकनीकें शामिल की जाती हैं। सम्मेलन में आईओटी सक्षम स्मार्ट अवसंरचना, स्मार्ट नगरों के डिजाइन व योजना निर्माण में आईओटी की भूमिका, एम-2-एम/आईओटी के मानकीकरण से संबंधित विविध आयाम तथा स्मार्ट डिवाइस/उपकरण की सुरक्षा, जांच व प्रमाणन की चुनौतियां जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
4. एम-2-एम/आईओटी का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों के विविध अनुप्रयोगों में हो रहा है, जैसे ओटोमोटिव (बुद्धिमत्ता पूर्ण परिवहन प्रणाली), ऊर्जा (स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ग्रिड), सुदूर क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा व निगरानी, स्मार्ट आवास, कचरा प्रबंधन तथा जल प्रबंधन आदि। स्मार्ट नगरों के डिजाइन और योजना निर्माण में ये सभी आयाम महत्वपूर्ण हैं।

नासा ने पृथ्वी से 3 गुना बड़ा ग्रह खोजा

नासा ने हमारे सौर मंडल के बाहर एक नया ग्रह खोज लिया है। इस नए ग्रहक को HD 21749 b नाम दिया गया है और इसकी खोज नासा के नए ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (जै)ने की है। प्लैनेट की खोज करने वाला नासा का यह नया टेलिस्कोप है। यह ग्रह पृथ्वी से 53 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी के इतने नजदीक होने के बावजूद यह काफी ठंडा है और इसका तापमान 300 डिग्री फरेनहाइट है।

क्या है

1. इस नए ग्रह की खोज करने वाली टीम की मुखिया और MIT के कावली इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रॉफिजिक्स एंड स्पेस रिसर्च की डायना ड्रैगॉमिर ने इस पर कहा, 'शुक्र जैसे चमकदार तारे का चक्कर कर रहा यह अब तक का सबसे ठंडा छोटा ग्रह है, जिसके बारे में हम अब जानते हैं।'
2. उन्होंने आगे बताया कि वैज्ञानिकों द्वारा छोटा कहे जाने के बावजूद, यह पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा है।
3. पृथ्वी की तुलना में नया HD 21749 b 3 गुना बड़ा है। अपने साइज के चलते यह सब-नेपच्यून कैटिगरी में आता है जिसका मतलब है कि यह जै द्वारा खोजा गया लगभग पृथ्वी के साइज वाला पहला ग्रह होगा।

सोलर सिस्टम में सबसे दूर पहुंचा नासा का स्पेसक्राफ्ट

भारत को गौरवान्वित करने वाला काम मुंबई के श्याम भासकरन ने कर दिखाया है। श्याम नासा के ऐतिहासिक फ्लाइबाय मिशन का हिस्सा थे जो 1 जनवरी को अज्ञात ऑब्जेक्ट अल्टिमा थुले के पास से गुजरा। अल्टिमा थुले हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित ऑब्जेक्ट है। न्यू होराइजन ने जनवरी 2006 को पृथ्वी से छोड़ा गया था। इस फ्लाइबाय मिशन को नैविगेट करने में भासकरन ने भी भूमिका निभाई। बता दें कि श्याम भासकरन नासा की जेट प्रोपल्शन लैबरेटरी में काम करते हैं। उनकी जन्म 1963 को मुंबई के माटुंगा में हुआ था। भासकरन इससे पहले भी नासा के कई मिशन को नैविगेट कर चुके हैं।

क्या है

1. अल्टिमा थुले पर रोशनी इतनी कम है और वह इतना दूर है कि वैज्ञानिकों को फिलहाल उसके साइज और शेप का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अब न्यू होराइजन के पास तक जाने से कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है क्योंकि वह उसकी कुछ तस्वीरें भी भेजेगा।
2. मिली जानकारी के मुताबिक, 1 जनवरी को न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने अल्टिमा थुले से करीब 3,500 किलोमीटर ऊपर उड़ान भरी। इससे पहले भासकरन ने नैविगेशन टीम से बात कर बताया था कि सब काम ठीक चल रहा है।
3. भासकरन 1968 में भारत छोड़कर यूएस शिफ्ट हुए थे। इस बीच वह 1981 में अपने रिश्तेदारों से मिलने वापस मुंबई भी आए थे। तब उन्होंने पाया था कि मुंबई पहले से मुकाबले काफी बदल गई है।
4. उस पल को याद करते हुए भासकरन ने कहा था, 'शमैंने देखा कि मुंबई एक बड़ा शहर हो गया था। वहां भीड़ काफी बढ़ गई थी। हां मैं दोबारा वहां जरूर जाना चाहूंगा।'

मिशन मून में देरी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद (इसरो) ने इस बात की पुष्टि की है कि वह आगामी 3 जनवरी को चंद्रयान-2 को लॉन्च नहीं करने जा रहा है। इसरो का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन का अंतरिक्षयान चांगी 4, 30 दिसम्बर 2018 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। चांगी 4 यान अब चंद्रमा के उस हिस्से में लैंड करेगा जिसकी अभी तक कोई पड़ताल नहीं हुई है। इससे पहले इसरो ने ऐलान किया था कि चंद्रयान-2 को जल्द ही लॉन्चे किया जाएगा। बता दें कि इसरो इस यान को जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहता है लेकिन अब तक उसने प्रक्षेपण की डेट फाइनल नहीं की है।

क्या है

1. गौरतलब है कि चांगी 4 और चंद्रयान-2 दोनों ही सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर उतरना चाहते थे। अब चीनी यान सबसे पहले चंद्रमा के पृथ्वीद से दूर वाले हिस्से में उतरेगा वहीं चंद्रयान-2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। चांद के इस हिस्से के बारे में अभी तक कोई पुख्तो जानकारी नहीं है।
2. चीन की शिन्हुगआ न्यूहज एजेंसी के मुताबिक चांगी 4 को योजना के मुताबिक कक्षा में पहुंच गया है। पहली बार चंद्रमा के सुदूरवर्ती इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग होगी। हालांकि एजेंसी ने यह नहीं बताया कि यह लैंडिंग कब होगी।
3. उधर, इसरो भी चंद्रयान-2 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जिसे इससे पहले वर्ष 2017 और फिर वर्ष 2018 में टाल दिया गया था। चंद्रमा के शर्क साइड में उतरने के लिए चंद्रयान-2 के पास अभी 16 फरवरी तक का समय है।
4. चंद्रयान-2 मिशन में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी और एक रोवर चंद्रमा के सतह की जांच और प्रयोग करेगा।

अंटार्कटिका की रहस्यमयी झील

अंटार्कटिका की एक रहस्यमयी झील को खोजने में वैज्ञानिकों ने कामयाबी हासिल कर ली है। यह झील आकार में मेनहट्टन से दोगुनी है। बर्फ से 3,500 फीट नीचे दबी और पानी से भरी इस झील को आधिकारिक रूप से सबग्लेसियल लेक मर्सर के नाम से जाना जाता है। करीब एक दशक पहले मर्सर सबग्लेसियल झील को पहली बार सैटेलाइट के जरिए खोजा गया था। तब इस झील को सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सिर्फ देखा गया था।

क्या है

1. रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 400 झील अंटार्कटिका की आइसशीट के नीचे दबी हुई हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि यहां जीवन की संभावनाएं मंगल, चंद्रमा, जूपिटर आदि ग्रहों पर भी जीवन होने की उम्मीद को जगा सकती हैं।
2. इस झील का पानी फिल्टर पानी जितना ही साफ है। दरअसल झील के पानी की स्वच्छता का परीक्षण भी ड्रिलिंग प्रोसेस का हिस्सा था। दो बार के परीक्षण में पानी को पूरी तरह साफ पाया गया।
3. मर्सर सबग्लेसियल सक्रिय झील है, जो पश्चिम अंटार्कटिका आइसशीट के फास्ट मूविंग सेक्शन द विलियंस आइस प्लेन के नीचे है।
4. द सबग्लेसियल अंटार्कटिका लेक्स साइंटिफिक एक्सेस (ऍसै) टीम के मुताबिक मर्सर सबग्लेसियल झील तक पहुंचने में दो दिन लगे।
5. टीम ने जमी हुई बर्फीली नदी में गर्म पानी ड्रिल के उच्च-दबाव के साथ पिघलाकर अपने लिए रास्ता बनाया। चार दिन की कड़ी मशक्कत के बाद ड्रिल टीम ने काम शुरू किया।
6. अगले कुछ दिनों में शोधकर्ताओं की टीम झील की गहराई, तापमान और साफ-सफाई पर अधिक अध्ययन करने की योजना बना रही है।

लद्दाख में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट

अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर लद्दाख अब जल्द ही एक नई वजह से जाना जाएगा। यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाए जाने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार, दक्षिणी करगिल से करीब 200 किलोमीटर दूर बनाए

जाने वाले इस प्लांट से बिजली उत्पादन के साथ ही एक साल में करीब 12,750 टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आसपास के इलाकों को रोजगार भी मिलेगा।

क्या है

1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन संस्था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ऀम्ब) इससे जुड़े प्रॉजेक्ट्स को प्रमोट कर रही है।
2. माना जा रहा है कि लद्दाख में 5,000 मेगावॉट की यूनिट और करगिल के लिए 2,500 मेगावॉट की यूनिट साल 2023 तक तैयार हो जाएगी। इस पर करीब 45,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
3. लद्दाख की प्रॉजेक्ट यूनिट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र लेह के न्योमा में हनले-खलदो में बनाई जाएगी। वहीं करगिल सोलर प्लांट यूनिट को जान्स्कार के सुरु में बनाया जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 254 किलोमीटर की दूरी पर है।
4. लद्दाख यूनिट से जनरेट होने वाली बिजली को कैथल तक सप्लाई किया जाएगा, जिसके लिए 900 किलोमीटर लंबी लाइन लेह-मनाली सड़क पर बिछाई जाएगी। करगिल परियोजना श्रीनगर के पास न्यू वानपोह में ग्रिड के साथ शुरू होगी। करगिल परियोजना श्रीनगर के पास न्यू वानपोह में ग्रिड के साथ जुड़ेगी।
5. एसईसीआई के डायरेक्टर एसके मिश्रा ने बताया कि टेंडर्स से जुड़ी समस्याओं पर गौर करने के साथ ही प्रॉजेक्ट के स्थान से जुड़ी समस्याओं पर भी गौर कर उन्हें दूर करने की कोशिश की गई है।
6. प्रॉजेक्ट से जुड़ी एक और सकारात्मक बात यह है कि लेह और करगिल प्रशासन ने पहाड़ी परिषदों के लिए शपारिश्रमिक कीमतों पर क्रमशः 25,000 और 12,500 एकड़ गैर-चरने वाली भूमि को नामित किया है, जो 3% वार्षिक वृद्धि के साथ प्रति वर्ष लगभग 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर का किराया भी कमाएगा।
7. प्रॉजेक्ट के लिए जमीन का चुनाव हो जाना संभावित प्रमोटर्स के लिए एक बड़ी राहत है, जो अलग-अलग स्थानों से साइट विजिट के लिए आ रहे हैं और प्रॉजेक्ट में काफी रुचि दिखा रहे हैं।
8. उम्मीद की जा रही है कि सोलर पैनल परियोजनाएं सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देंगी और स्थानीय लोगों को सोलर पैनलों की सफाई और ट्रांसफार्मर का रखरखाव आदि जैसे कौशल सिखा कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाएंगी।

चंद्रमा पर रातें क्यों होती हैं सर्द

चीन का चंद्र रोवर 'चांग ई-4' रात के दौरान चंद्रमा पर रहने वाले जमाव बिंदु के तापमान का पता लगाएगा। इस मून मिशन का नाम 'चांग ई-4' चीनी पौराणिक कथा अनुसार चंद्रमा देवी पर रखा गया है। धरती से कभी न दिखने वाले चंद्रमा के पिछले हिस्से पर यह यान 3 जनवरी को उतरा था। यह अब तक पहला यान है जिसे चंद्रमा के सबसे अछूते हिस्से पर उतारा गया है। चांग ई-4 के सफल प्रक्षेपण को खगोलीय अवलोकन की दिशा में चीन की एक लंबी छलांग माना जा रहा है और इससे अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की दिशा में उसकी महत्वाकांक्षाओं को काफी बल मिला है। चूंकि चंद्रमा का परिक्रमा चक्र और घूर्णन चक्र समान होता है इसलिए धरती से चंद्रमा का एक ही पक्ष हमेशा दिखता है और इसके दूसरे पक्ष के अधिकतर हिस्से को नहीं देखा जा सकता है।

क्या है

1. धरती से नजर नहीं आने वाले चंद्रमा के उस पक्ष को ही डार्क साइड कहते हैं। यानी अंधकार की वजह से नहीं बल्कि अज्ञात एवं अनछुआ होने के चलते इसे शडार्क साइड कहा जाता है। चंद्रमा पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है और रात भी उतनी ही लंबी होती है।
2. चांद पर दिन और रात के तापमान में भीषण अंतर होता है। वैज्ञानिकों का आकलन है कि दिन के दौरान अत्यधिक तापमान 127 डिग्री सेल्सियस के आस पास जबकि रात का तापमान शून्य से 183 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच सकता है।

3. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार 2013 में चीन ने चांग ई-3 का प्रक्षेपण किया था। पिछले पांच साल में 60 चंद्र रात्रि से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इसके वैज्ञानिक उपकरण अब भी वहां अपने लैंडर पर ठीक अवस्था में कार्यरत हैं।
4. चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (सीएएसटी) से चांग ई-4 अन्वेषण परियोजना की कार्यकारी निदेशक झांग हे ने सिन्हुआ को बताया, शयं सफलता तो है लेकिन चांग ई-3 को तापमान आंकड़े के हिसाब से डिजाइन किया गया था।
5. चंद्रमा के तापमान के बारे में अपने आंकड़े के बगैर हम नहीं जान पाते कि चंद्रमा पर रातों वास्तव में कितनी सर्द हो सकती है। चांग ई-4 चंद्रमा पर दिन और रात के तापमान के बीच के अंतर को मापेगा, जिससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह की प्रकृति के आकलन में मदद मिलेगी।

6 गुना तेजी से पिघल रही है अंटार्कटिका में बर्फ

अंटार्कटिका में बर्फ 1980 की तुलना में 6 गुना तेजी से पिघल रही है। एक नए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों ने ऊपर से ली गई तस्वीरों, उपग्रह माप और कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल कर यह पता लगाया कि 1979 से अंटार्कटिका पर बर्फ कैसे पिघल रही है। उन्होंने पाया कि बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है और मानवीय कारणों से होने वाला जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण है।

क्या है

1. मनुष्य पर्यावरण को नष्ट कर रहा है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे और इसका दंड मनुष्य को अवश्य मिलेगा
2. अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका में 2009 से हर साल 278 अरब टन बर्फ पिघल रही है, जबकि 1980 के दशक में 44 अरब टन बर्फ पिघल रही थी।
3. बर्फ पिघलने की हालिया औसत दर पिछले साल के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक एरिक रिगटन ने बताया कि उपग्रह आधारित अध्ययन में बड़ा अंतर यह दिखाई दिया कि स्थिर समझे जाने वाले पूर्वी अंटार्कटिका में भी एक वर्ष में 56 अरब टन बर्फ पिघल रही है।

विविध

स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का शुभारंभ

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप एस. पुरी ने आधिकारिक तौर पर 5 जनवरी 2018 नई दिल्ली में शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के चौथे संस्करण 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2019' का शुभारंभ किया। इस वर्ष यह सर्वेक्षण 4 से 28 जनवरी, 2019 के दौरान 4237 शहरों और कस्बों में कराया जाएगा। यह सर्वेक्षण पूरी तरह से डिजिटल एवं कागज रहित (पेपरलेस) होगा और इसे 28 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में पूरा किया जाएगा। शहरों में बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जनवरी, 2016 में 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2016' कराया था, जिसमें 73 शहरों की रैंकिंग की गई थी। इसके बाद जनवरी-फरवरी, 2017 के दौरान 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2017' कराया गया था जिसके तहत 434 शहरों की रैंकिंग की गई थी। सर्वेक्षण का तीसरे चरण अर्थात् 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2018' बड़े पैमाने पर कराया गया था। इसके तहत 4203 शहरों एवं कस्बों में सर्वेक्षण कराया गया था जिसे 66 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में पूरा किया गया। इसके साथ ही यह विश्व में अब तक का सबसे व्यापक स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया जिसके दायरे में लगभग 40 करोड़ लोग आए।

क्या है

1. इस अवसर पर श्री हरदीप एस. पुरी ने बताया कि किसी स्वतंत्र थर्ड पार्टी द्वारा कराए जाने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण का उद्देश्य बड़े पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कचरा मुक्त एवं खुले में शौच मुक्त शहरों की दिशा में की गई पहलों की निरंतरता सुनिश्चित करना, किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) के प्रमाणन द्वारा सत्यापित कराए

- जाने वाले विश्वसनीय निष्कर्ष उपलब्ध कराना, ऑनलाइन प्रक्रियाओं के जरिये वर्तमान प्रणालियों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना और शहरों एवं कस्बों को लोगों के रहने की दृष्टि से बेहतर बनाने की दिशा में काम करने के बारे में समाज के सभी तबकों के बीच जागरूकता पैदा करना है।
2. इस सर्वेक्षण का एक उद्देश्य शहरों एवं कस्बों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है, ताकि वे स्वच्छ शहरों के निर्माण की दिशा में नागरिकों को बेहतर ढंग से सेवाएं मुहैया कराने की ओर अग्रसर हो सकें।
 3. एसबीएम (स्वच्छ भारत मिशन) ओडीएफ+ और एसबीएम ओडीएफ++ की दिशा में विभिन्न शहरों में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया है।
 4. जहां एक ओर एसबीएम ओडीएफ+ का उद्देश्य शौचालयों की स्वच्छता एवं रखरखाव को सुनिश्चित करते हुए उनके उपयोग को निरंतर जारी रखना है, वहीं दूसरी ओर एसबीएम ओडीएफ++ के तहत मल के सुरक्षित एवं समुचित प्रबंधन सहित संपूर्ण स्वच्छता मूल्य श्रृंखला के जरिये स्वच्छता को निरंतर बनाए रखने पर फोकस किया जाता है।
 5. अभी तक 7 शहरों (इंदौर, उज्जैन, खरगोन, शाहगंज, राजनंदगांव, अंबिकापुर और भिलाई) को ओडीएफ++ और 35 शहरों को ओडीएफ+ घोषित या प्रमाणित किया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की मुख्य बातें

1. यह ऑनलाइन एमआईएस के जरिये पूरी तरह से डिजिटल सर्वेक्षण होगा।
2. 4 बड़े स्रोतों यथा 'सेवा स्तर पर प्रगति', प्रत्यक्ष अवलोकन, नागरिकों से मिली प्रतिक्रिया और प्रमाणन से आंकड़ों का संग्रह किया जाएगा।
3. 'सेवा स्तर पर प्रगति' के तहत विभिन्न अवयवों को संशोधित भारांक (वेटेज) दिया जाएगा। इसके अलावा एक नया अवयव 'उप नियम' जोड़ा जाएगा।
4. प्रमाणन (कचरा मुक्त शहरों और खुले में शौच मुक्त प्रोटोकॉल की स्टार रेटिंग) : आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरों के 'प्रमाणन' का एक महत्वपूर्ण अवयव शुरू किया है।

सेना के बेड़े में शामिल होंगी धनुष और सारंग

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर और फील्ड गन फैक्ट्री में तैयार 'धनुष (बभ्रुवृक्ष)' और 'सारंग (तिलछल्ल)' जल्द सैन्य बेड़े में शामिल होंगी। फरवरी में एक भव्य समारोह में दोनों को औपचारिक रूप सेना में शामिल किया जाएगा। दोनों ही गन सेना के हर परीक्षण में पूरी तरह से खरी उतरी हैं। बोफोर्स तोप (इतववितबम) की जगह 'धनुष को तैनात करने का काम शुरू हो चुका है। पूरी तरह से स्वदेशी 'धनुष तोप दुनिया की सबसे मारक तोपों में से एक है। बोफोर्स की तुलना में इसकी मारक क्षमता 18 किलोमीटर ज्यादा है। अभी 414 तोप बनाने का लक्ष्य है लेकिन ये संख्या और बढ़ेगी। 'धनुष' की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे 31 साल पुरानी बोफोर्स की जगह तैनात किया जाएगा। सेना को देने से पहले इससे 2000 राउंड फायर किए गए। सेना ने भी हरी झंडी देने से पहले सियाचीन और राजस्थान में करीब 1500 राउंड टेस्ट फायर किए, तब इसे अपने बेड़े में शामिल किया।

क्या है

1. सारंग तोप रूसी तोप एम-46 टाउड को रिप्लेस करेगी। यह तोप 1968 से सेना के पास है। इसका कैलिबर 130 एमएम है। इसे ओएफसी और फील्डगन फैक्ट्री कानपुर मिलकर तैयार करेंगे।
2. सारंग इजरायली तोप सॉल्टम का ही आधुनिक संस्करण है। इसकी कैलिबर 135 अब 155 एमएम की गई है।
3. मार्च 2018 में हुए कई परीक्षणों में इस तोप ने भारत फोर्ज और पुंजलॉयड की तोपों को पछाड़ कर ओपेन बिड में सेना से ऑर्डर हासिल किया था। वर्ष 2022 तक तीन सौ तोपों का निर्माण कर सेना को दिया जाना है।

धनुष की यह खासियत

1. धनुष देश की पहली तोप है जिसमें 90 फीसदी कलपुर्जे भारत में बने हैं

पांच तोपों में भारत का धनुष

1. बोफोर्स बीओ-5 - स्वीडन
2. एम 46- एस - इजरायल
3. जीसी 45 - कनाडा
4. नेक्सटर - फ्रांस
5. धनुष - भारत

2. बैरल का वजन 2692 किलो
3. रेंज 46 किलोमीटर तक
4. दो फायर प्रति मिनट में दो घंटे तक लगातार फायर करने में सक्षम
5. तीन फायर प्रति मिनट में डेढ़ घंटे तक लगातार फायर
6. 12 फायर प्रति मि. कर सकती धनुष
7. फिट होने वाले एक गोले का वजन 46.5 किलो
8. माइनस 3 से 55 डिग्री सेल्सियस तक काम करने में सक्षम
9. धनुष का बैरल रूसी और यूरोपियन टेक्नोलॉजी को मिला तैयार किया गया, किसी भी सूरत में फटेंगे नहीं

सारंग की खासियत

1. 70 डिग्री तक मूव किया जा सकता है
2. पहाड़ों में छिपे दुश्मनों को तबाह करने की विशेष क्षमता

देश में पहली बार होगी ओपन यूनिवर्सिटीज की ग्रेडिंग

देश में पहली बार मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए होने वाली ग्रेडिंग का मानक इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने तैयार किया है। 60 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार मानक इग्नू ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) को सौंपी है। संभावना है कि इसी के अनुसार, देश के सभी मुक्त विश्वविद्यालयों पर मानक लागू हों। अभी नैक लोगों से इसपर राय लेगा, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। इग्नू के कुलपति प्रो. नागेश्वर राव ने बताया कि अब तक मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए मानक का कोई आधार नहीं था। मुक्त विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम है। इसे लागू करने के बाद गुणवत्ता के साथ संबंधित संस्थान की छात्रों के प्रति जिम्मेदारी तय होगी।

क्या है

1. सरकार ने सभी मुक्त विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कोर्स संचालित करने की भी अनुमति दी है, लेकिन अधिकांश में ऑनलाइन कोर्स बेहतर ढंग से संचालित नहीं होते हैं। लेकिन, ग्रेडिंग सिस्टम के तहत बेहतर ग्रेडिंग पाने वाले विश्वविद्यालय बेहतर ऑनलाइन कोर्स भी संचालित कर सकेंगे, क्योंकि उनके यहां बेहतर फैकल्टी शिक्षण और प्रशिक्षण में संबद्ध होंगे।
2. इग्नू द्वारा बनाए गए मानक एक हजार अंकों में बांटे गए हैं। सात मानकों में सबसे अधिक शिक्षण एवं मूल्यांकन पर अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका ग्रेडिंग के दौरान सर्वाधिक महत्व है।
3. कुल 250 अंकों में इसे बांटा गया है। इसमें 30 अंक छात्र जहां पढ़ रहे हैं, उससे संतुष्टि से भी जुड़ा है। यहां पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान दिया गया है।
4. माना जाता है कि वहां संस्थान में पढ़ रहे छात्रों की फीडबैक से ग्रेडिंग स्तर को और मजबूती मिलेगी। साथ ही शिक्षकों की बेहतर गुणवत्ता का फायदा भविष्य में यहां दाखिला लेने वाले छात्रों को सीधे तौर पर मिलेगा।
5. इसलिए 60 सदस्यीय समिति द्वारा तय मानक में रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन में भी शिक्षकों के शोध, प्रकाशन और अवार्ड के लिए अंकों का विशेष निर्धारण किया गया है।

सीजीपीए ग्रेड

1. 3.51-4.00 ए प्लस प्लस.
2. 3.26-3.50 ए प्लस.
3. 3.01-3.25 ए.
4. 2.76-3.00 बी प्लस प्लस.
5. 2.51-2.75 बी प्लस.
6. 2.01-2.50 बी.
7. 1.51-2.00 सी.

8. 1.50 से कम डी .

ये हैं सात मानक

1. करिकुलर एस्पेक्ट्स.
2. टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्युएशन.
3. रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन.
4. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्स.
5. लर्नर सपोर्ट एंड प्रोग्रेसन.
6. गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट.
7. इंस्टीट्यूशन वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिस.

देश में पहली बार अनोखा प्रयोग

वनों की बहुलता वाले राज्य में पौधरोपण के नाम पर रही लगातार शिकायतों को दूर करने के लिए वन विभाग ने एक अभिनव प्रयोग किया है। अब पौधरोपण व पौधों के रखरखाव की मॉनिटरिंग सेटेलाइट आधारित डेस्कबोर्ड के माध्यम से होगी। वन विभाग ने लगभग छह माह की मशक्कत के बाद इस डेस्कबोर्ड सिस्टम को तैयार किया है। अगले 15 दिन में यह सिस्टम कार्य करने लगेगा।

क्या है

1. वन विभाग में पौधरोपण के क्षेत्रफल, पौधों की संख्या, उनके जीवित रहने की स्थिति को लेकर अक्सर अलग-अलग रिपोर्ट विभाग के सामने आते थे। विभाग इसको लेकर बड़ा असहज रहता था। ऐसे में कुछ अधिकारी विभाग को गुमराह कर ऐसे स्थानों पर पौधरोपण की रिपोर्ट देते थे, जहां की मॉनिटरिंग संभव ही नहीं था।
2. वन विभाग ने अब सेटेलाइट आधारित डेस्कबोर्ड बनाकर पौधरोपण की नियमित मॉनिटरिंग करने का रास्ता निकाला है। अब राज्य में जहां भी पौधरोपण होगा, वहां की जीपीएस लोकेशन फीड की जाएगी और रायपुर में बैठा अधिकारी बस्तर के घोर इलाके में हुए पौधरोपण को सीधा देख सकेगा।
3. एक-एक पौधे की संख्या के गिना जा सकेगा। एक वर्ष में कितने पौधे रोपित किए गए। कितने पौधे बचे और कितने नष्ट हो गए, इसकी गणना भी इस सिस्टम को माध्यम से हो जाएगी।
4. डेस्कबोर्ड के माध्यम से पौधरोपण के तीन वर्षीय अभियान को भी व्यवस्थित किया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव वन सीके खेतान ने बताया कि यह सिस्टम वन विभाग में पौधरोपण की समस्या का संपूर्ण समाधान है।
5. अपने तरह का यह राज्य ही नहीं देश भर में पहला अभिनव प्रयोग है। इसी महीने इस सिस्टम का टेस्ट किया जाएगा और इसे तत्काल लागू किया जाएगा।

आईसीडीएस योजना के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी 07 जनवरी 2018 को 97 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वर्ष 2017-18 हेतु उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार भी उपस्थित होंगे। भारत सरकार ने वर्ष 2000-2001 में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यूएस) को पुरस्कृत करने के लिए एक योजना का शुभारंभ किया था।

क्या है

1. यह पुरस्कार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने और आईसीडीएस योजना के तहत बाल विकास और उससे संबंधित क्षेत्रों में अनुकरणीय सेवा देने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस वर्ष से राष्ट्रीय स्तर पर नकद पुरस्कार की धनराशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।
2. दिशानिर्देशों के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा नामित पुरस्कार विजेताओं को दिया जाता है।

3. राष्ट्रीय स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नामांकन की संख्या राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और परिचालित आईसीडीएस परियोजनाओं के आकार पर निर्भर करती है। पुरस्कारों की संख्या को भी दोगुना कर दिया गया है।
4. इन पुरस्कारों के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त नामांकन की जांच की जाती है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा इनकी सिफारिश की जाती है। पुरस्कार विजेताओं का चयन माननीय महिला और बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति के द्वारा किया जाता है।
5. राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार में 50,000 रुपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जबकि राज्य स्तर के पुरस्कार में 10,000 रुपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

भारत ने रचा इतिहास रचा

भारतीय क्रिकेट टीम ने 71 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए आस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली बार टेस्ट श्रृंखला जीतकर अपने क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर चौथा और अंतिम टेस्ट मैच खराब मौसम और बारिश के कारण ड्रा छूटा और इस तरह से भारत श्रृंखला 2-1 से अपने नाम करने में सफल रहा। इसके साथ ही उसने बोर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने पास बरकरार रखी। भारत ने 2017 में अपने घरेलू मैदानों पर श्रृंखला 2-1 से जीतकर यह ट्रॉफी जीती थी। भारत ने स्वतंत्रता मिलने के कुछ दिन बाद पहली बार 1947-48 में लाला अमरनाथ की अगुवाई में आस्ट्रेलिया का दौरा किया था। तब उसका सामना सर डान ब्रैडमैन की अजेय आस्ट्रेलियाई टीम से था। तब से लेकर अब जाकर भारत का श्रृंखला जीतने का इंतजार विराट कोहली की टीम ने खत्म किया।

1. भारत के पास श्रृंखला 3-1 से जीतने का मौका था लेकिन बारिश ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत ने अपनी पहली पारी सात विकेट पर 622 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी जिसके जवाब में आस्ट्रेलिया 300 रन पर आउट हो गया और उसे अपनी धरती पर पिछले 30 साल में पहली बार फालोआन के लिये उतरना पड़ा। आस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के छह रन बनाये।
2. इस जीत को भारत की विदेशों में ऐतिहासिक विजय में शामिल किया जाएगा। इसे अजित वाडेकर की टीम की 1971 में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में, कपिल देव की टीम की 1986 में इंग्लैंड में और राहुल द्रविड़ की अगुवाई वाली टीम की 2007 में इंग्लैंड में जीत की बराबरी पर रखा जाएगा।
3. भारत ने चौथे टेस्ट मैच से पहले श्रृंखला में 2-1 की अजेय बढ़त बना ली थी। भारतीय टीम ने एडिलेड में पहला टेस्ट मैच 31 रन से जीता था। आस्ट्रेलिया ने पर्थ में दूसरे टेस्ट मैच में 146 रन से जीतकर वापसी की लेकिन भारत ने मेलबर्न में तीसरा मैच 137 रन से अपने नाम करके इतिहास रचने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाये थे।
4. भारत अब इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप की तैयारियों में जुट जाएगा। इसकी शुरुआत वह आस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे श्रृंखला से करेगा।

आईएमएफ के शीर्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला

भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ ने अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) के चीफ इकॉनमिस्ट का पदभार ग्रहण कर लिया है। आईएमएफ के शीर्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला हैं। उन्होंने मौरी ओब्सफेल्ड की जगह ली है, जो पिछले वर्ष 31 दिसंबर को रिटायर हो गए। गीता का जन्म भारत के मैसूर में हुआ है। अक्टूबर में गीता गोपीनाथ के नियुक्ति के बारे में बताते हुए आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा था शशीता दुनिया के बेहतरीन अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। उनके पास शानदार अकादमिक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और व्यापक अंतरराष्ट्रीय अनुभव है। शशी आईएमएफ में इस पद पर पहुंचने वाली गीता दूसरी भारतीय हैं। उनसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी आईएमएफ में प्रमुख अर्थशास्त्री रह चुके हैं।

क्या है

1. आईएमएफ के 11 वें मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त गोपीनाथ ने द हार्वर्ड गजट को हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में बताया कि आईएमएफ में उनकी नियुक्ति प्जबरदस्त सम्मान है। आईएमएफ के नेतृत्व में उनकी नियुक्ति दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक आदर्श है।

2. गोपीनाथ के मुताबिक, अधिकांश देश डॉलर में अपना व्यापार करते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में उधार लेते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय मूल्य प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का एक केंद्रीय हिस्सा है जिसे आईएमएफ के साथ मिलकर इसके परिणामों का पता लगाना रोमांचक होगा।
3. गीता गोपीनाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से एमए की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्रिंसटन विश्वविद्यालय से 2001 में प्राप्त की। इसके बाद उसी साल उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम शुरू कर दिया।

विश्व हिंदी दिवस

विश्व हिंदी दिवस (World Hindi Day) मनाने की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक दशक पहले 10 जनवरी, 2006 को की थी, तभी से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल मनाए जाने वाले विश्व हिंदी दिवस का असल मकसद दुनियाभर में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए वातावरण बनाना और हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी के लिए अनूठे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस कड़ी में अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पहली बार भारतीय कांसुलेट (वाणिज्य दूतावास) में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा।

क्या है

1. विदेश में भारत के दूतावास विश्व हिंदी दिवस विशेष रूप से मनाते हैं। सरकारी कार्यालयों में हिंदी में व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं।
2. पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 तक नागपुर में आयोजित हुआ था। इसका बोधवाक्य था - वसुधैव कुटुंबकम।
3. दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरीशस में हुआ। मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई में 28 अगस्त से 30 अगस्त 1976 तक यह चला।
4. विश्व हिंदी सम्मेलन देश की राजधानी दिल्ली में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 1983 तक किया गया।
5. 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन अगस्त 2018 में मॉरीशस में आयोजित किया गया।
6. हर साल 14 सितंबर को शहिन्दी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था।

यहां से निकली हिंदी

1. प्रख्यात भाषाविज्ञानी हरदेव बाहरी अपनी किताब (हिंदी भाषा) में लिखते हैं कि विकास के क्रम में भारतीय आर्यभाषा को तीन कालों में बांटा जाता है।
2. प्राचीन (वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत)- 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व
3. मध्यकालीन (पालि, प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट)- 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक
4. आधुनिक (हिंदी और हिंदीतर भाषाएं - बांग्लाट, उडि़या, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी सिंधी आदि)-1000 ईसवी से।

पहली बार जैविक सीवर लाइन का फॉर्मूला

सीवर लाइन चोक होने से फैलने वाली गंदगी के दंश से जूझ रहे देश के नगर निगमों को जल्द राहत मिल सकती है। ग्वालियर के एक जुझारू अफसर ने देश में संभवत पहली बार जैविक सीवर लाइन का फॉर्मूला तैयार किया है। 20 तरह के बैक्टीरिया को डेवलप कर तैयार किया गया एक विशेष घोल 48 घंटे के अंदर चोक सीवर लाइन को खोल सकने में सक्षम होगा। ग्वालियर नगर निगम ने इस विशेष घोल की टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो सीवर लाइन चोक रहने की बड़ी समस्या गुजरे दिनों की बात हो जाएगी। फॉर्मूला खोजने वाले ग्वालियर जिला पंचायत के यह

प्रोजेक्ट ऑफिसर जय सिंह नरवरिया पहले भी देशभर में सबसे सस्ते बायोटॉयलेट का फॉर्मूला दे चुके हैं। बायोटॉयलेट में उपयोग होने वाले बैक्टीरिया से ही यह आयडिया उन्हें मिला।

क्या है

1. प्रोजेक्ट ऑफिसर जय सिंह नरवरिया के अनुसार बायोटॉयलेट वाले बैक्टीरिया को डेवलप किया गया है। इसमें 20 तरह के बैक्टीरिया हैं, जिनका एक सम्मिश्रण तैयार किया गया है।
2. इस बैक्टीरिया को एनाबोरिक माइक्रोबिअल कंसोसिएशन नाम दिया गया है। चोक पड़े सीवर को एक तरह से काटते हुए यह लाइन क्लियर कर देगा। सीवर में डालने के 48 घंटे में बैक्टीरिया अलर्ट हो जाता है और काम शुरू करता है।
3. प्रोजेक्ट ऑफिसर जयसिंह नरवरिया की माने तो पूरी दुनिया में बैक्टीरिया आधारित फॉर्मूले का उपयोग नहीं होता है। विश्वभर के चुनिंदा विशेषज्ञों से जय सिंह नरवरिया ने खुद बात की, लेकिन कहीं भी यह बैक्टीरिया आधारित फॉर्मूले की जानकारी नहीं मिली।
4. जय सिंह नरवरिया ने महज 10 से 12 हजार रुपये में तैयार बायोटॉयलेट का फॉर्मूला देश को दिया था, जिसे प्रशासन सहित दूसरे राज्यों में भी पसंद किया गया। इसके लिए कई राज्यों ने उनसे संपर्क भी किया है।
5. नरवरिया ने अपने घर और आसपास इस बैक्टीरिया को ट्रायल के तौर पर सीवर लाइन में डाला। सैंपल ट्रायल में यह सफल रहा। अब नगर निगम कमिश्नर विनोद शर्मा से बात कर इस फॉर्मूले को शेयर किया गया है और शहर का एक ऐसा वार्ड मांगा गया है, जहां सीवर चोक की समस्या ज्यादा रहती है। निगम कमिश्नर ने सहमति दे दी है और जल्द इसका बड़े लेवल पर प्रयोग किया जाएगा।
6. सस्ते बायोटॉयलेट का फॉर्मूला देने वाले जिला पंचायत के प्रोजेक्ट ऑफिसर ने हमसे सीवर की समस्या से ग्रस्त एक वार्ड मांगा गया है। उन्हें वार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। यदि ट्रायल सफल होता है तो यह हमारे लिए बड़ी राहत लेकर आयेगा।

‘बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय विमर्श’ का आयोजन

साल के पहले ‘बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय विमर्श’ का आयोजन 8 जनवरी को इंडिया हैबिटेड सेंटर, नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में किया गया। विमर्श का आयोजन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बाल संरक्षण संस्थाओं की निगरानी की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के लिए किया गया था। इसमें बाल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी लेने के साथ ही बाल संरक्षण संस्थाओं में सुधार के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदम का जायजा लिया गया।

क्या है

1. इस बैठक में 33 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, राज्यों के महिला और बाल विकास विभाग या सामाजिक कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ नोडल पुलिस अधिकारी (महिला और बाल विकास के लिए) मौजूद रहे।
2. बैठक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के प्रतिनिधियों के साथ ही 17 राज्यों के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के प्रतिनिधि, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए), राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) और चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (सीआईएफ) के अलावा मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे।
3. सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने, बाल विकास समिति (सीडब्ल्यूसी) और किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) की रिक्तियों को भरने के साथ ही इसके लिए उठाए गए दूसरे कदमों की जानकारी दी।
4. आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने बताया कि वो संस्थानों को ग्रेड देने की शुरुआत कर चुके हैं। राज्यों ने ये भी सूचित किया कि उन्होंने बाल संरक्षण संस्थानों को चलाने वाले संगठनों की पृष्ठभूमि की जांच और वहां कार्य करने वालों का पुलिस सत्यापन भी शुरू कर दिया है।

5. महिला और बाल विकास, राज्य पुलिस विभाग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग समेत बाल संरक्षण से जुड़ी सभी संस्थाओं को मिलकर कार्य करने को लेकर भी बातचीत हुई। इससे बाल संरक्षण गृह की निगरानी संभव हो सकेगी।
6. महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना करने के साथ ही उन्हें सावधान भी किया कि इस संबंध में लगातार निगरानी करते रहना होगा ताकि बच्चों का हित सुरक्षित रहे।

आइआइटी के साथ बनेगा मास्टर प्लान

केंद्र सरकार प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए आइआइटी के साथ मास्टर प्लान तैयार कर सकती है। आइआइटी के पूर्व छात्र एवं केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक पद्मश्री के. विजय राघवन ने यह संकेत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूर्व छात्र एसोसिएशन की बैठक में दिए। प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए अब तक जो शोध कार्य हुए हैं, उनका आकलन किया गया है। इसमें कई बिंदु सामने आए हैं, जिन पर काम कर शहर की दूषित आबोहवा बदली जा सकती है।

क्या है

1. के. विजय राघवन आइआइटी कानपुर में प्रदूषण पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में छात्रों से भी रूबरू हुए। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप भागवत ने बताया कि मुख्य वैज्ञानिक ने प्लान तैयार करने के लिए दिल्ली में बैठक बुलाई है।
2. शोध के जो बिंदु चिह्नित हुए हैं, उनमें एयर सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एयर प्यूरीफाई डिवाइस, कार्बन कटर, नैनोटेक मास्क, इंडोर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्रदूषण नियंत्रण यूनिट शामिल हैं।
3. आइआइटी ने इनमें से कई उत्पाद व उपकरण बना लिए हैं। इसके अलावा मुंबई, पुणे, बंगलुरु और हैदराबाद समेत देशभर में शोध कर रहे पूर्व छात्र अपने उपकरणों के साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे।
4. प्रदीप भागवत ने बताया कि आइआइटी छात्रों के स्टार्टअप में भारत व विदेश में कार्यरत पूर्व छात्र मदद करेंगे। छात्र जो स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं, उनके क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने का पूरा प्रयास होगा। इस बिंदु पर भी कार्ययोजना तैयार की गई है।

प्रदूषण पर अब राज्यों को भी दिखानी होगी सख्ती

बढ़ते प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने की मुहिम में केंद्र सरकार ने राज्यों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत उन्हें सभी जिलों और नगरीय क्षेत्रों में इससे निपटने के लिए हार्डपावर कमेटी गठित करने को कहा है। साथ ही प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़े कदम भी उठाने को कहा है। अभी प्रदूषण से निपटने के लिए ऐसी कमेटी सिर्फ केंद्र और राज्य स्तर पर ही मौजूद है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक प्रदूषण का स्तर जिस तरीके से देश के सभी शहरों में तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके तहत जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित होगी, जबकि नगरीय क्षेत्रों में निगमायुक्त की देखरेख में यह कमेटी काम करेगी। मौजूदा समय में केंद्र स्तर पर पर्यावरण मंत्रालय के सचिव और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ऐसी कमेटी गठित है।

क्या है

1. राज्यों को दिए गए निर्देश में मंत्रालय का निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने को लेकर पूरा जोर है। इसके तहत हवा की गुणवत्ता को जांचने के लिए सभी जिलों और शहरों में ज्यादा से ज्यादा उपकरण लगाने को कहा गया है, ताकि प्रदूषण के बढ़ते स्तर की सटीक जानकारी मिल सके।
2. मंत्रालय की मानना है कि जब तक प्रदूषण के बढ़ते स्तर और कारणों की जानकारी नहीं होगी, तब तक उपाय करना मुश्किल है। मौजूदा समय में देश के करीब दो सौ जिलों में ही हवा की गुणवत्ता को जांचने की सटीक व्यवस्था उपलब्ध है।
3. मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक जिलों और नगरीय क्षेत्रों में ऐसी कमेटियों के गठन के बाद हर महीने उनके कामों की समीक्षा भी होगी। फिलहाल यह काम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख में होगा।

4. खासबात यह है कि जिला स्तर पर गठित होने वाली हाईपावर कमेटी में जिला स्तर पर तैनात प्रदूषण बोर्ड का अधिकारी भी शामिल होगा। मौजूदा समय में इसका काम सिर्फ कागजों तक ही सिमटा हुआ है।

इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में भारत ने दिया निवेश निमंत्रण

नीति आयोग के प्रधान सलाहकार अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि भारत 2030 तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का लक्ष्य हासिल करना चाहता है और भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार के विस्तार में वह चीन के उद्योग की प्रतिभागिता और निवेश का स्वागत करता है। श्रीवास्तव अपने साथ एक उद्योग प्रतिनिधिमंडल लेकर चीन पहुंचे हैं। उन्होंने 11-13 जनवरी को आयोजित 'ग्लोबल जीरो इमीशन एंड ऑल इलेक्ट्रिक वेहिकल' सम्मेलन को संबोधित किया।

क्या है

1. विश्व के दो बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक चीन और भारत बिजली वाहनों के निर्माण में संयुक्त उद्यम के लिए उत्सुक हैं। दोनों देशों ने पेइचिंग में आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन में इसके लिए वार्ता की।
2. मारुति सुजुकी, टाटा, टीवीएस जैसे भारत के दिग्गज ऑटोमेकर और उद्योग संघों ने पेइचिंग में 5वें चीनईवी100 फोरम में भागीदारी की। इस फोरम में दुनियाभर की ई-वाहन निर्माता कंपनियां मौजूद थीं।
3. 13 जनवरी 2018 को समाप्त हुए तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन चीन ईवी100 ने किया था, जो कि चीनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उद्योग की 200 से ज्यादा दिग्गज कंपनियों का एक निजी बिजली वाहन संघ है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष नीति आयोग के प्रधान सलाहकार अनिल श्रीवास्तव ने चीनईवी100 के अध्यक्ष चेन किंगताई से मुलाकात की।
4. मैकिन्से के मुताबिक, चीन बिजली वाहनों की मांग और आपूर्ति दोनों में एक दिग्गज के रूप में उभरा है। हालांकि कुछ चीनी कंपनियों का मानना है कि भारत इन वाहनों की मांग के संदर्भ में चीन को पछाड़ देगा। इससे पहले आईएनएस के साथ एक साक्षात्कार में चीन की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी सुनरा के महाप्रबंधक विक्टर लु ने कहा कि वे भारत को इलेक्ट्रिक बाइक के लिए विश्व के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरते हुए देखते हैं।
5. फोरम को संबोधित करते हुए श्रीवास्तव ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य के रोडमैप के लिए भारत की नीति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक पर्यावरण प्रतिबद्धताओं के लिए प्रतिबद्ध है और वह स्वच्छ ऊर्जा व नई ऊर्जा परिवहन के विकास व उसे अपनाने को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत द्वारा 2030 तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में चीनी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं।
6. दोनों देशों के ईवी उद्योगों के बीच अधिक बातचीत होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच एक औपचारिक बातचीत तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बीजिंग में इस साल की पहली छमाही में दोनों पक्षों के बीच एक बैठक करने का भी प्रस्ताव रखा, ताकि सहयोग की संभावनाओं को तलाशा जा सके।
7. श्रीवास्तव के साथ बैठक के बाद चेन ने कहा कि चीनी बिजली वाहन कंपनियों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश है और उन्होंने भारतीय बाजार में चीनी उद्योगों को भागीदारी और निवेश के लिए प्रोत्साहित किया।

छठा महिला जैविक उत्सव सम्पन्न

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे देश में महिला जैविक उत्सवों के आयोजन के जरिये महिला किसानों और उद्यमियों को और अधिक खरीदारों से जोड़ने की कोशिशों को बढ़ावा देने में लगा है। यह बात महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने चंडीगढ़ में आयोजित छठे महिला जैविक उत्सव के समापन के मौके पर विभिन्न स्टालों और फूड कोर्ट के दौरे के बाद कही। श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि इस उत्सव के जरिये मंत्रालय महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न पहलों और योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है।

क्या है

1. महिला **जैविक उत्सव का आयोजन** 2015 से हर साल नई दिल्ली में होता रहा है और इस बार महिला किसानों और उद्यमियों के विभिन्न उत्पादों को सामने लाने के लिए चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया।
2. इससे जहां महिलाओं को वित्तीय समावेशन के जरिये सशक्त किया जाएगा वहीं भारत में जैविक खेती को बढ़ावा भी मिलेगा।
3. तीन दिनों के इस उत्सव में **देश के विभिन्न भागों से आई 200 से अधिक महिला** किसानों और उद्यमियों ने फूड कोर्ट में 15 फूड स्टालों के अलावा विभिन्न कृषि और जैविक उत्पादों के लिए 72 स्टाल लगाए।
4. श्रीमती मेनका गांधी ने बेहतर, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के लिए देश भर में जैविक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया।

पीएम को मिला फिलिप कोटलर अवॉर्ड

पीएम नरेंद्र मोदी को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए फिलिप कोटलर प्रेजिडेंशियल अवॉर्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी को दिल्ली में यह सम्मान दिया गया। यह पुरस्कार हर साल दुनिया के किसी एक राष्ट्राध्यक्ष को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण **संरक्षण के क्षेत्र में योगदान** के लिए दिया जाता है।

क्या है

1. पीएमओ ने बताया कि अवॉर्ड देने वाली संस्था के मुताबिक देश का शानदार नेतृत्व करने के लिए मोदी को यह सम्मान दिया गया है।
2. उन्हें दिए गए प्रशस्ति पत्र में लिखा गया, श्रमरत की स्वार्थरहित सेवा और अथक ऊर्जा के साथ काम करने के चलते देश ने आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक क्षेत्र में अप्रत्याशित प्रगति की है।
3. यही नहीं पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल कैम्पेन की सराहना करते हुए उन्हें विजयरी लीडर करार दिया गया है।

क्रिएटिव सामानों के निर्यात में भारत शीर्ष देशों में शामिल: रिपोर्ट

भारत रचनात्मक वस्तुओं के निर्यात में दुनिया के शीर्ष दस विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो गया है। हिंदुस्तान से रचनात्मक वस्तुओं के निर्यात में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है और यह 2005 में 7.4 अरब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2014 में 20.2 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। यूनाइटेड नेशन (यूएन) के एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। **रचनात्मक सामानों के निर्यात और आयात में चीन अकेला सबसे बड़ा देश** है। यूएन की व्यापार और विकास (यूएनसीटीएडी) रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2015 के बीच रचनात्मक वस्तुओं में चीन का व्यापार हर साल 14 फीसद की दर से बढ़ा है। यह आंकड़ा 2002 से 2015 की अवधि का है।

क्या है

1. इस अवधि के दौरान रचनात्मक वस्तुओं के लिए वैश्विक बाजार का मूल्य 2002 में 208 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना होकर 2015 में 509 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
2. रिपोर्ट के अनुसार, रचनात्मक सामानों के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने में चीन, हांगकांग (चीन), भारत, सिंगापुर, चीन के ताइवान प्रांत, तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया, मैक्सिको और फिलीपींस जैसे शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं।
3. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका, फ्रांस, इटली, यूके, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम और जापान शीर्ष 10 रचनात्मक सामान निर्यातक थे।

4. रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का रचनात्मक सामान निर्यात का आंकड़ा 2005 में 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2014 में 20.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
5. 2014 में रचनात्मक वस्तुओं के निर्यात में डिजाइन किए गए सामान का सबसे ज्यादा असर रहा और यह 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया।
6. आभूषणों का निर्यात 13.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसके बाद फैशन का सामान 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
7. 2005 में रचनात्मक सामान के निर्यात में यूएस भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार था, लेकिन 2014 में यूई के साथ आने से यह दूसरे नंबर पर फिसल गया।